

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मचा घमासान

» इंडिया गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की...

» जो दिल्ली में हुआ, वो मुंबई में भी हो सकता है... संजय राउत ने क्यों कहा ऐसा...

» संजय राउत की दो टूक, स्थानीय चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं...

» इंडिया गठबंधन की

कमजोरी के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार

» दिल्ली में अलग-अलग लड़ रही हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस

नई दिल्ली/मुंबई, 12 जनवरी 2025 (ए)। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की राजनीति में हलचल मची है। इसके केंद्र में है कांग्रेस। दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। इससे इंडिया गठबंधन पर सवाल



उठने लगे हैं। ताजा खबर महाराष्ट्र से है। यहां शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि बीएमपी (ब. ह. मु. ब. इ. महानगर पालिका) सहित महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले ही संजय राउत ने पार्टी मुखपत्र सामना में लिखा था कि जो दिल्ली में हो सकता है, वो मुंबई में भी हो सकता है। शनिवार सुबह संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि

क्या हो रहा दिल्ली में

दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। उम्मीद की जा रही थी कि आप और कांग्रेस मिलकर भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उल्टा, आप और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस के लिए हालात तब और मुश्किल हो गए, जब इंडिया गठबंधन के अन्य दलों जैसे सपा और टीएमसी ने खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का एलान कर दिया।

सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण इंडिया गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं बुला सकी है। बकौल संजय राउत, यह सच है

कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बनाया गया था, लेकिन हम अब तक संयोजक की घोषणा नहीं कर पाए हैं। अगर हमें किसी ताकत के खिलाफ लड़ना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा।



कांग्रेस का शिक्षित बेरोजगारों के लिए अप्रेंटिसशिप का वादा

हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपये नई दिल्ली, 12 जनवरी 2025 (ए)। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक गारंटी का एलान कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने रविवार को तीसरी गारंटी की घोषणा की है। यह घोषणा युवाओं के लिए की गई है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर दिल्ली के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपये प्रति महीने देने की बात कही है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

महत्वपूर्ण खबर

विजय कुमार बनेंगे दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर



नई दिल्ली, 12 जनवरी 2025 (ए)। जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) विजय कुमार अब दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह पिछले पांच सालों से कश्मीर घाटी में जम्मू-कश्मीर पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है।

चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के खिलाफ 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, 12 जनवरी 2025 (ए)। उच्चतम न्यायालय बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में चुनाव नियम, 1961 में संशोधन को चुनौती दी गई है। ये नियम कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रोकें जाने को लेकर है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ 15 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी।

जाति जनगणना पर सीएम सिद्धरमैया का बड़ा संकेत

अगली कैबिनेट बैठक में पेश हो सकती है रिपोर्ट

विजयनगर, 12 जनवरी 2025 (ए)। देश की राजनीति में इस समय जाति जनगणना की चर्चा काफी जोरों से हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहा है। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने एक अलग संकेत दिया।

कर्नाटक के सीएम ने रविवार को संकेत दिया कि जाति जनगणना रिपोर्ट को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें पिछले



साल रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाना है। इस पर हमने 160 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। देखते हैं कैबिनेट में इस पर क्या चर्चा और फैसला होता है।

पिछले साल मिली थी रिपोर्ट

वहीं, जब पत्रकारों ने जाति जनगणना का विरोध करने वाले लोगों के बारे में पूछा तो कर्नाटक के सीएम ने कहा कि

जाति जनगणना और आरक्षण का या तो समर्थन होगा या विरोध होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े ने 29 फरवरी, 2024 को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी है। इसे आमतौर पर जाति जनगणना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। इसने विभिन्न पिछड़े समुदायों के बीच बहस छेड़ दी है तथा कुछ ने इसका विरोध किया है। राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने दो जनवरी को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में जाति जनगणना पर चर्चा होगी।

भाजपा को वोट दिया तो एक साल में आपकी झुगियां उजाड़ देंगे : अरविंद केजरीवाल



नई दिल्ली, 12 जनवरी 2025 (ए)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को शंकरपुर बस्ती स्थित झुग्गी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसवार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे-वैसे भाजपा का झुगियां को लेकर प्रेम बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि

अगर दिल्ली के झुग्गीवालों ने भाजपा को वोट दे दिया, तो ऐसा करके आप लोग अपनी आत्महत्या पर साइन कर देंगे। ये लोग आप लोगों को मार देंगे। ये लोग आपकी झुग्गी को तोड़ देंगे। इन लोगों ने सारी प्लानिंग कर रखी है। पिछले दस सालों में भाजपा ने तीन लाख लोगों को बेघर कर दिया है। आप नेता ने कहा कि आज मैं अमित शाह को चैलेंज करने वाला हूँ। अमित शाह जी ने दस सालों में जितनी झुग्गीवालों को उजाड़ा है, उन सभी केस को कोर्ट से वापस ले लें। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि जितनी झुग्गियां तोड़ी हैं, उनको वापस बसाएंगे। आपने जिन-जिन लोगों को उजाड़ा था, उन्हें उसी जमीन पर वापस नहीं लाते, तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह अमीरों की पार्टी है। इन लोगों ने पिछले पांच-दस सालों में आज तक झुग्गीवालों की सुध नहीं ली, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इनके नेता झुग्गी में जाकर सो रहे हैं। ये लोग तो झुग्गीवालों को कोड़े-मकोड़े समझते हैं।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र से मदद मांगी

हैदराबाद, 12 जनवरी 2025 (ए)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद को एक वैश्विक शहर के रूप में विकसित करने और हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण सहित राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए



पूर्व राज्यपाल सीएच विद्यासागर राव की आत्मकथा यूनिफा के विमोचन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे तेलंगाना को देश में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने में सहयोग करें।

गन प्वाइंट पर चुनाव जीतने की कोशिश हो तो कार्यकर्ता लें फैसला



लखनऊ, 12 जनवरी 2025 (ए)। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हर हाल में चुनाव जीतेगी। लेकिन अगर गन प्वाइंट पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई तो उनके कार्यकर्ता उस समय जो फैसला ले सकते हैं, वह लें, इस बात को मन में रखें। रविवार को सपा मुखिया अखिलेश

यादव लखनऊ में विवेकानंद की जयंती पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव में गन प्वाइंट पर गड़बड़ी की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, उस समय जो फैसला ले सकते हैं, लें। भाजपा ने अपने विभागों के लूटने वाले मंत्रियों को वहां ड्यूटी पर लगाया है। सपा मुखिया ने कहा कि इस बात को अपने मन में रखें, इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। जिस राज्य में भाजपा के खिलाफ जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, उसका साथ दिया जाना चाहिए।

प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत

छात्राओं की उतरवाई शर्ट, सिर्फ ब्लेजर पहनाकर भेजा घर

धनबाद, 12 जनवरी 2025 (ए)। झारखंड के धनबाद में एक स्कूल प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 10 वीं की छात्राओं के पेपर खत्म होने के बाद पेन ड्रे मंनाने के दौरान प्रिंसिपल ने गुरुसे में आकर छात्राओं की शर्ट उतरवा दी और उन्हें सिर्फ ब्लेजर पहनकर घर भेज दिया। इस घटना की जानकारी जब छात्राओं के परिजनों को हुई, तो



वे काफी आक्रोशित हो गए और धनबाद के डीसी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इस कृत्य के लिए प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद डीसी माधवी मिश्रा ने मामले की जांच का आदेश दिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस कृत्य को लेकर पूरे राज्य में बवाल मच गया है। अभिभावक इसे

तालीबानी मानसिकता से जोड़ते हुए दोषी प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले के संबंध में छात्राओं और उनके अभिभावकों से भी बातचीत की। यह पूरा मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है। हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमने इस संबंध में जांच कमेटी बनाई है, जो स्कूल में जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे।

कोलकाता रेप-मर्डर मामले में बाँडी पर मिला 4 लोगों का डीएनए

वकील बोले सीबीआईने फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं किए...

कोलकाता, 12 जनवरी 2025 (ए)। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर का केस फिर उलझ गया है। अब सीएफ एसएल की रिपोर्ट से पता चला है कि ट्रेनी डॉक्टर की बाँडी पर कई लोगों का डीएनए मिला है। इनमें एक महिला भी हो सकती है। ट्रेनी डॉक्टर की डेडबॉडी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी।

सीएफ एसएल रिपोर्ट में लिखा है कि क्राइम सीन पर विक्टिम और आरोपी के बीच संघर्ष के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं, मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड यानी सीएफ एसएल की रिपोर्ट में आया था कि ट्रेनी डॉक्टर ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया था।



यही सवाल विक्टिम फैमिली के वकील ने भी उठाया है। उनका दावा है कि विक्टिम के बालों में

बलचर लगा था। इसका सबूत भी है। यह बलचर मौके से रिकवर की गई 40 चीजों में शामिल नहीं था। इससे शक होता है कि क्राइम कहीं और हुआ है। फोरेंसिक जांच करने वाले एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संजय अकेला

अपराधी भी हो सकता है। हालांकि इसमें डीएनए एक्सपर्ट की राय लेना भी जरूरी है। जांच के लिए भेजे गए कुछ सैंपल में मिलावट मिली है। इससे दूसरे लोगों की मौजूदगी का पता लगा पाना मुश्किल है। विजरा और फिंगर प्रिंट ने कोर्ट में जवाब नहीं दिया है। सीबीआई ने 35 लोगों की लिस्ट बनाई है। ये लोग शक के दायरे में हैं। ये लोग कौन हैं, ये पता नहीं चला है। संजय के वकील का आरोप है कि सीबीआई सभी सदिग्धों को पेश नहीं कर रही है।

मिनी बस बेकाबू होकर खाई में गिरी, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

पौड़ी, 12 जनवरी 2025 (ए)। पौड़ी से सेंट्रल स्कूल जाने वाले मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक बस दुर्घटना हुई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। दुर्घटना बस संख्या यूके-12पीबी 0177 की है, जो अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हृदय से गहरा शोक

व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यह बस पौड़ी शहर से देहलचौरी की ओर जा रही थी। सत्याखाल के पास बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। गिरते समय बस पेड़ से टकराई, जिससे वह और नीचे जाने से रुक गई। हालांकि, हादसे के कारण बस के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में सवार यात्रियों की

चौख-पुकार सुनकर तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय ग्रामीणों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। घायलों को खाई से निकालने के लिए



रस्सियों और अन्य उपकरणों का सहारा लिया गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर

किया गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार, हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान की जा रही है। वहीं, घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। उतराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पौड़ी में केंद्रीय विद्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर बस के

दुर्घटनाग्रस्त होने से चार यात्रियों के निधन का अत्यंत दुःख समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को शांति और परिजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफस-तफरी मच गई। स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर घायलों को खाई से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं।

संपादकीय

लोगों का प्रति महीने उपभोग खर्च बढ़ा

बड़े उपभोग खर्च में महंगाई की भी एक भूमिका है। सरकार की ओर से मासिक उपभोग खर्च के बारे में जारी आंकड़ों से आंकना कठिन है कि कितना उपभोग बढ़ा और कितनी वृद्धि उपभोग की चीजों की महंगाई के कारण हुई। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग सर्वेक्षण (एमपीसीई) रिपोर्ट तो कुछ पहले आई थी, लेकिन अब केंद्र ने इसकी एक तथ्य तालिका जारी की है। इसमें भी वही दिखाने की कोशिश है कि अगस्त 2023 से सितंबर 2024 की अवधि में उसके पहले वाले वर्ष की तुलना में लोगों का प्रति महीने उपभोग खर्च बढ़ा। स्पष्टतः सरकार इसे शहर से गांवों तक में आय और खुशहाली बढ़ने के प्रमाण के रूप में पेश किया है। मगर जो सवाल सर्वे रिपोर्ट जारी होने के समय उठे, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है। विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि सबसे ज्यादा खर्च खाद्य पदार्थों पर बढ़ा। जिस अवधि में यह सर्वे हुआ, उसमें खाद्य मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही। फिर पुगने सर्वेक्षणों की तुलना में सर्वे विधि में जो परिवर्तन किए गए, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह आंकना और मुश्किल हो गया है कि लोगों के उपभोग पैटर्न में सचमुच कितना बदलाव आया। खुद ताजा रिपोर्ट से ही जाहिर हुआ कि टॉप 10 प्रतिशत आबादी के उपभोग में पर्याप्त वृद्धि हुई, जबकि सबसे निचली पांच फीसदी आबादी के वास्तविक खर्च में बढ़ोतरी मद्धम रही। निचली आर्थिक श्रेणी की आबादी में जो वृद्धि देखी है, उसमें बड़ा योगदान सरकार की तरफ से दिए जा रहे पांच किलो अनाज और प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजनाओं का है। जाहिर है, इसे कमाई से होने वाली आमदनी की स्थिति में सुधार नहीं कहा जा सकता। एक अन्य तथ्य यह सामने आया है कि ग्रामीण इलाकों में जो उपभोग खर्च बढ़ा, खाद्य के अलावा उसका सबसे बड़ा हिस्सा इलाज, परिवहन, वस्त्र और जूते-चप्पल के हिस्से में गया। इन चीजों की महंगाई के कारण हुई। ये सारे उल्लेख सरकार की नकारात्मक छवि बनाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। मगर अपने आंकड़ों को लेकर विश्वास का संकेत खुद सरकार ने खड़ा किया है।

रिटायर्ड अफसरों के बोझ तले दबा आरटीआई का ढाँचा



डॉ सत्यवान सौरभ बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा

सेवानिवृत्त अधिकारी उन विभागों के खिलाफ निर्णय लेने में संकोच कर सकता है, जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया था, जिससे समझौतापूर्ण फैसले होते हैं। पारदर्शिता में विशेषज्ञता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान की कमी हो सकती है, जो आरटीआई अधिनियम का मुख्य हिस्सा है। सेवानिवृत्त नौकरशाह वर्तमान सामाजिक मुद्दों से कटे हुए हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आने वाले सूचना आयुक्त समकालीन दृष्टिकोण से सूचना तक पहुंचने के बारे में जनता की चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। लंबे समय तक सरकारी सम्बद्धता वाले नौकरशाहों की नियुक्ति से जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि उनके निर्णय सरकारी हितों के साथ संरक्षित हो सकते हैं। विशेष राजनीतिक दलों

से सम्बंध रखने वाले नौकरशाह सरकारी निर्णयों को चुनौती देने में अनिच्छा दिखा सकते हैं, जिससे आरटीआई ढांचे की स्वतंत्रता कम हो सकती है। भारत में सूचना आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के प्रभुत्व ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) ढांचे की स्वतंत्रता और विविधता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। जबकि उनका अनुभव मूल्यवान हो सकता है, इस ने संभावित पूर्वाग्रहों और सीमित प्रतिनिधित्व पर बहस छेड़ दी है। इस तरह के प्रभुत्व के निहितार्थ और उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड को व्यापक बनाने का पता लगाता है। आरटीआई ढांचे में स्वतंत्रता और विविधता के बारे में कई चिंताएँ हैं। सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का प्रभुत्व एक संकीर्ण, एकरूप दृष्टिकोण बनाता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविधता को कम करता है। सेवानिवृत्त नौकरशाहों का अक्सर प्रतिष्ठान का हिस्सा माना जाता है, जिससे सरकार की कार्यवाहियों को निष्पक्ष रूप से चुनौती देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। पूर्व सरकारी कर्मचारी अपने पूर्व सहयोगियों के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे अपीलों को संभालने में निष्पक्षता कम हो सकती है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी उन विभागों के खिलाफ निर्णय लेने में संकोच कर सकता है, जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया था, जिससे समझौतापूर्ण फैसले होते हैं।



पारदर्शिता में विशेषज्ञता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान की कमी हो सकती है, जो आरटीआई अधिनियम का मुख्य हिस्सा है। सेवानिवृत्त नौकरशाह वर्तमान सामाजिक मुद्दों से कटे हुए हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आने वाले सूचना आयुक्त समकालीन दृष्टिकोण से सूचना तक पहुंचने के बारे में जनता की चिंताओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। लंबे समय तक सरकारी सम्बद्धता वाले नौकरशाहों की नियुक्ति से जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि उनके निर्णय सरकारी हितों के साथ संरक्षित हो सकते हैं। विशेष राजनीतिक दलों से सम्बंध रखने वाले नौकरशाह सरकारी निर्णयों को चुनौती देने में अनिच्छा दिखा सकते हैं, जिससे आरटीआई ढांचे की स्वतंत्रता कम हो सकती है।

सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के प्रभुत्व का प्रभाव पड़ता है। जब चयन पूल में विविधता का अभाव होता है, तो जनता आरटीआई ढांचे की तटस्थता में विश्वास खो सकती है। सीमित नए दृष्टिकोण वाले नौकरशाहों का प्रभुत्व अक्षमता में योगदान देता है, जिससे आरटीआई अपीलों के प्रसंस्करण में देरी बढ़ जाती है। सीआईसी के 23, 000 अपीलों का बैकलॉग बताता है कि नए दृष्टिकोण के बिना नौकरशाही नियुक्तियाँ नागरिक शिकायतों के समय पर समाधान में बाधा बन सकती हैं। नियुक्तियों में विविधता की कमी के परिणामस्वरूप समान पृष्ठभूमि वाले कुछ व्यक्तियों के हथों में शक्ति केंद्रित हो जाती है। यह प्रथा नवीन विचारों या दृष्टिकोण में परिवर्तन को रोकती है जो आरटीआई अधिनियम की प्रभावकारिता में सुधार कर सकते हैं। विविध इनपुट के बिना, आरटीआई ढांचा आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होने में विफल हो सकता है, जिससे सुधार रुक सकते हैं जो इसे और अधिक

प्रभावी बना सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि निर्णय पक्षपातपूर्ण हैं या पूर्व सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रभावित हैं, तो वे आरटीआई प्रक्रिया से जुड़ने के लिए कम इच्छुक महसूस कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के पूल को व्यापक बनाने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। विभिन्न विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को शामिल करने से निर्णय लेने में व्यापक दृष्टिकोण आएगा। यह आरटीआई ढांचे में विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। यूके जैसे देशों में, सूचना आयुक्त कानून, पत्रकारिता और शिक्षा जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं। एक सार्वजनिक, पारदर्शी चयन प्रक्रिया निष्पक्षता को बढ़ावा देगी और सभी को सूचना आयुक्त की भूमिकाओं के लिए आवेदन करने का समान अवसर देगी। अमेरिका कई सरकारी निगरानी भूमिकाओं के लिए एक सार्वजनिक नामांकन प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कार्यकाल सीमित करने और आयु प्रतिबंध लागू करने से नए दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है और सूचना आयोगों के भीतर गतिशील नेतृत्व की अनुमति मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई राष्ट्र वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करते हैं ताकि दीर्घकालिक रूप से जनता से बचा जा सके और नए विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आरटीआई प्रणाली जनता की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य शामिल हैं, जो विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति अपने दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। आवेदनों के लिए आउटरीच और जागरूकता का विस्तार करना- रिक्रियों को सक्रिय रूप से प्रचारित करना और आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ाना विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि से उम्मीदवारों को आकर्षित करने में मदद करेगा, जिससे अधिक विविध पूल बनेंगे। न्यूजीलैंड जैसे देश सार्वजनिक क्षेत्र की रिक्रियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों से कुशल पेशेवर आकर्षित होते हैं। आरटीआई ढांचे की स्वतंत्रता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए, सुधार आवश्यक है। निविध क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल करके पात्र उम्मीदवारों के पूल का विस्तार करने से नए दृष्टिकोण आ सकते हैं, पूर्वाग्रह कम हो सकते हैं और जवाबदेही बढ़ सकती है। अधिक समावेशी दृष्टिकोण प्रणाली की पारदर्शिता को मजबूत करेगा, जिससे दीर्घकालिक रूप से जनता का विश्वास बढ़ेगा।

किसानों की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं



किसानों ने धरना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उन्हें पिछली बार की तरह दिल्ली की सीमा तक नहीं पहुंचने दिया गया। उन्हें पंजाब की सीमा पर ही रोक दिया गया। किसान साल भर से वहीं धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं हुई। तब कैबिनेट पीटित 70 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 26 नवम्बर को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। सरकार के कान पर तो फिर भी जू नहीं रेंगी, मगर जब अनशन को करीब एक महीने बीत गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। उसने पंजाब सरकार को कहा कि वह डल्लेवाल को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराए, लेकिन डल्लेवाल इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं वे चिकित्सकीय सुविधा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी किसान सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाने की दिशा में सार्थक पहल करना चाहता है तो उसे पंजाब सरकार की बजाय केंद्र सरकार को हिदायत या आदेश देना चाहिए। आखिर कृषि का मसला पंजाब सरकार से तो जुड़ा नहीं है। यह केंद्र का मामला है। केंद्र की सरकार ने ही पहले मांगें मानी थीं। उसे ही इस पर अमल करना है। अपने आंदोलन को गति देने के लिए किसानों ने बीती चार जनवरी को एक महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में एक लाख से ज्यादा किसान जुड़े। इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान तो थे ही देश के बाकी हिस्सों से भी किसान पहुंचे। पिछली बार के आंदोलन से सबक लेते हुए किसान दो-तीन दिन पहले ही महापंचायत स्थल पर पहुंच गए थे। इस महापंचायत में डल्लेवाल भी स्टूचर पर लाए गए। उन्होंने थोड़ी देर किसानों को संबोधित भी किया। इस बीच सरकार ने अपना पुराना खेल शुरू कर दिया है। किसानों में फूट डालने वाली। जहां वे पंचायत हुई उसके बगल में ही उसी दिन एक दूसरी पंचायत भी हुई। कहा जा रहा है कि ये पंचायत सरकार के इशारे पर की गई और किसान आंदोलन के विरुद्ध बातें की गईं। दूसरी तरफ सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार इस नई पॉलिसी के जरिए एक बार फिर से निरस्त किए गए तीनों कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से वापस लाना चाहती है। केंद्र ने इस पॉलिसी को विचार के लिए सभी राज्यों को भेजा है। किसान भी इस पॉलिसी को लेकर सशक्त और सतर्क हैं।

अमेरिकी शर्तों के प्रति भारत का सतर्क रुख

अमेरिकी विदेश नीति अमेरिकी प्रभुत्व पर आधारित रही है जिसमें इस तथ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि विदेशों में अग्रणी भूमिका बनाए रखने में कौन सा देश उसका सबसे ज्यादा सहयोगी है तथा इस भागीदारी को और कैसे पुख्ता किया जा सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की विदेश नीति मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति पर आगे बढ़ने से संकोच नहीं करती, यह सामरिक, आर्थिक या राजनैतिक हो सकता है। इस समय भारत और अमेरिका के संबंधों को इतिहास का बेहतरीन दौर बताया जा रहा है, लेकिन असल में कूटनीतिक वास्तविकताएं अविश्वास की खाई को पाट नहीं सकती हैं। इतिहास को पीछे छोड़कर दोनों देशों के शीर्ष राजनेता एक दूसरे के प्रति सार्वजनिक आलोचनाओं से परहेज भले ही करें, साझेदारी की अमेरिकी शर्तों के प्रति भारत का सतर्क रुख अमेरिकी नीति-निर्माताओं को असहज कर रहा है। दरअसल, वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत ने 2023 के मालदीव चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी तथा मोदी सरकार भारत समर्थक इब्राहिम सोलह को राष्ट्रपति बनाए रखना चाहती थी। इस रिपोर्ट का खंडन भारत और मालदीव दोनों देशों द्वारा किया गया। सूचना युद्ध उन्नत युद्धक्षेत्र प्रबंधन रणनीतियों का एक हिस्सा है। शांति काल में इसका लक्ष्य विदेशी देश में जनता की राय को प्रभावित करना होता है। अमेरिका और रूस के बीच सूचना युद्ध की तीव्रता भले ही अत्यधिक हो, भारत को लेकर भी अमेरिकी कूटनीति की भूमिका बेहद आक्रामक नजर आती है। अमेरिका का सूचना और खुफिया तंत्र खालिस्तानी आतंकवाद, कनाडा और मानवाधिकारों को लेकर भारत विरोधी रूख अपनाता रहा है। पिछले साल सितम्बर में प्रधानमंत्री मोदी कांडा शिखर सम्मेलन में भाग लेते अमेरिका पहुंचे थे, उसके कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी अधिकारियों ने खालिस्तान आंदोलन के समर्थक सिखों के एक समूह से मुलाकात की थी। इस दौरान व्हाइट हाउस ने उन्हें अपनी धरती पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय आक्रमण से सुरक्षा का आसन भी दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना की जरूरत को भारत के द्वारा अमेरिकी

प्रशासन के सामने रखने के बाद भी हसीना की सरकार का तख्तापलट और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां भारत के लिए बेहद प्रतिकूल दिखाई दे रही है। शेख हसीना की सरकार के समय में अमेरिका की भूमिका को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। अमेरिका ने भारत के हितों को नजरअंदाज कर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी, भारत इस प्रकार की अमें रि की कोशिशों का विरोध करता रहा। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भारत का सांस्कृतिक प्रभाव रहा है और इसका असर राजनीतिक परिस्थितियों पर भी पड़ता है। इन देशों में भारत की मजबूती से चीन के हित प्रभावित होते हैं, लेकिन इन देशों में अमेरिका भारत से जिस प्रकार की साझेदारी की इच्छा रखता है, भारत के लिए उस पर आगे बढ़ना सामरिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। अमेरिका हिन्द-प्रशात की रणनीति के केंद्र में भारत को आगे रखने की कोशिशें करता रहा है, वहीं भारत ने चीन को लेकर वैसी आक्रामकता नहीं दिखाई है, जिसकी अमेरिका ने अपेक्षा की थी। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में यह उल्लेख किया गया है, चीन इंडो-पैसिफिक में अमेरिका को विस्थापित करना चाहता है और अपने राज्य-संचालित आर्थिक मॉडल की पहुंच को विस्तार करना चाहता है। चीन सैन्य, आर्थिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इसकी तकनीकी महत्वकांक्षाएं इसके सैन्य विकास से अदृष्ट रूप से जुड़ी हुई हैं। भारत चीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का विरोध तो करता है, लेकिन इसे युद्ध की लड़ाई से बचाने वाली अमेरिकी योजनाओं का भाग बनने को वच बिल्कूल तैयार नहीं है। एशिया में अमेरिकी प्रभाव को आगे बढ़ाने में दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की महत्त्वपूर्ण भागीदार अवश्य हो, लेकिन इन देशों के चीन से मजबूत आर्थिक संबंध हैं। ये देश अमेरिका के चीन को लेकर आर्थिक अलगाव की नीति से इत्तेफाक रखते

हुए आगे बढ़ते कभी नहीं दिखाई दिए। वहीं भारत की आर्थिक और सामरिक चुनौतियों में अमेरिका ने अक्सर ढूँढ़ने की अक्सर कोशिश की है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए वह भारत पर दबाव बढ़ाने की कूटनीति आजमाता रहता है, हालांकि भारत की सामरिक स्वायत्तता की नीति भी अमेरिका को परेशान करती रही है। भारत द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को विच सित करने और पार पारिक सुरक्षा खतरों के खिलाफ कठोर शक्ति का निर्माण करने पर अधिक तत्काल ध्यान केंद्रित करना चाहता है। भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से भारत के रूस ज्यादा अहम हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र भारत अपनी विविधता और संप्रभुता को ध्यान में रखकर कूटनीतिक कदम उठाता है। सैन्य संबंधों से समान दूरी प्रारम्भ से ही भारत की गुटनिपेक्ष नीति रही है। भारत ये मानता है कि आर्थिक विकास की तेज गति हासिल करने के लिए उसे किसी गठबंधन व्यवस्था के खांचे से दूरी बनाकर रखनी होगी। दक्षिण एशिया को लेकर कई बार अमेरिका की व्यापक नीति, भारत के मूलभूत हितों से अलग होती है। भारत की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी पर रूस का प्रभाव है। तकनीकी हस्तांतरण को लेकर रूस ने भारत पर जो भरोसा दिखाया है, वह अमेरिका ने कभी नहीं दिखाया। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने के बाद भी भारत इस बात को लेकर अशंकाित रहता है कि वह सुरक्षा प्रतिष्ठान को प्रतिबंधित भी कर सकता है। पिछले साल अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। 2023 में भी एक भारतीय कंपनी पर रूसी सेना की मदद करने के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका हिन्द-प्रशात में अपनी रणनीति को प्रभावी कोयलता, पेट्रोल जैसे जीवाश्म इंधनों को प्राप्त करने में विफल इसलिए है क्योंकि वह भारत का भरोसा नहीं जीत पाया है। जाहिर है बेहतर

परिणामों के लिए अमेरिका को भारत और भारत के पड़ोसी देशों में अवांछित हस्तक्षेप की नीति से बचना होगा।

-डॉ. ब्रह्मदीप अलुने-

कविता
आगे छेरछेरा के तिहार

घटती-घटना
अशोक पटेल
तुम्हा शिवरीनारायण छतीसगढ़

पूरा महीना के पुत्री संगी महानदी के गंगा-धार जोंक-पैरी-महानदी के संगम डुबकी लगावो बार-बार। दान-पुण्या-दया-धरम के कथा-कहनी हे अपरम्पार मया-पिरित के एह बंधना जेना दिखत हे सुभर सार। छतीसगढ़ के पावन-भुइयॉँ किसम-किसम के तिहार जन-जन के जिनगी म बसे अउ इही हर आय आधार। पूरा-पुत्री के बेरा हर आगे आगे छेरछेरा के तिहार खोर-गली किंजर-किंजर के सब मागे जाथे दुवार-दुवार। मुर्ग-लाई के गुरहा लाडू नाहे लईका मन ल भाय छेरछेरा-छेरछेरा कहिके हित-मीत के घर-घर जाय। किंजर के संगी उंडा नाचय अउ सैंगवारी कुहकी माय झंझ-मंजीरा-मांदर घुडकय कर्मा-ददरिया तान सुनावय। छेरछेरा परब, हमर संस्कृति खेती-पाती हमर चिन्हरी हमर पुरखा के एह धरोहर इही आय हमर जेवनहारी।

वर्ष 2015 का पेरिस जलवायु सम्मेलन धरा के तात्परान को औद्योगिक चरण के आने के पहले के स्तर से 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए हुआ था। चूँकि पृथ्वी की गर्मी बढ़ते कुल गैसीय उत्सर्जनों में कार्बन डाई ऑक्साइड लगभग 70 प्रतिशत है। अतः ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री से ग्रे तक सीमित रखने के लिए 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर पहुंचने का लक्ष्य भी वैश्विक स्तर पर अपना लिया गया है, परंतु विडंबना है, और कटु यथार्थ भी कि इसे पाने के औजार के रूप में एक ट्रेडिंग गतिविधि को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी क्रम में 10-24 नवम्बर के बीच वाशिंगटन में कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करना बड़ी उपलब्धि माना गया है। कॉप-29 को तो वित्तीय कॉप भी कहा गया था और कार्बन ट्रेडिंग भी वित्तीय गतिविधि ही है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन उत्सर्जनों को हटाने और नये कार्बन उत्सर्जनों को न पहुंचने देना प्रोत्साहित हो इसके लिए 2015 में पेरिस समझौते में स्पष्ट कर दिया गया था कि

2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर पहुंचने का लक्ष्य

कार्बन को देशों या संस्थाओं के बीच खरीदा-बेचा जा सकता है। इस लेन-देन को कार्बन क्रेडिट के रूप में परिभाषित कर हस्तांतरणीय दस्तावेज बना कर स्थापित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के बयोटो प्रोटोकॉल (1997) और फिर 2005 में कार्बन को खरीदने-बेचने या व्यापार की जा सकने योग्य सामग्री पहले ही करार दिया जा चुका था किंतु पेरिस समझौते के अंतर्गत जो एक नया ज्यदा सुदृढ़ कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाए जाने की आवश्यकता थी, वह शुरूआती हस्ताक्षर के बाद कॉप-29 में हो सका। निरस्तदेह इस अभूत कार्य के रहते भी देशों के भीतर और देशों के बाहर कार्बन ट्रेडिंग हो रही थी किंतु एकरूप मानक न होने तथा पारदर्शिता के अभाव से अनेकों छूटो कार्बन क्रेडिटों का विश्व स्तर पर लेन-देन भी हो रहा था। ऐसे में लाखों और अरबों डॉलर के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी भी हुई। स्वीडिश कार्बन



बाजार में सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट वो ही जो अवनत वनों के कार्बन अवशोषक के रूप में सुधार, पुनर्स्थापना के लिए दिए जाते हैं। किंतु ये सबसे ज्यादा विवादों में भी रहते हैं। वन स्थितियों की बेसलाइन में छेड़छाड़ से ज्यादा कार्बन ऑफसेट दिखाया जा सकता है। जितना कार्बन हटाने का क्रेडिट लिया था उतना

कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे हटा ही नहीं था। कॉप-29 के पहले नेचर पत्रिका में ऐसी परियोजनाओं का अध्ययन प्रकाशित हुआ था, जिन्होंने करीब एक अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड के समतुल्य का कार्बन क्रेडिट कमाया था। उसमें से 15 प्रतिशत कार्बन ही कम किया था। अब खराब

और अच्छे गुणवत्ता में कार्बन क्रेडिटों का वर्गीकरण या पहचान भी की जा रही है। कार्बन ट्रेडिंग में कार्बन क्रेडिटों के लेन-देन का व्यापार होता है। कार्बन क्रेडिट की एक इकाई एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से हटाने या उनको वायुमंडल में पहुंचने से रोकने पर दी जाती है। कार्बन ऑफसेट में कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों को हटाना या पुनर्चक्रित किया जाता है। जो उद्यम अथवा प्रतिष्ठान उपकरणों, पद्धतियों या टेक्नोलॉजी के बदलावों से अपने कार्बन उत्सर्जन पहले की अपेक्षा कम कर देते हैं तो वे भी कार्बन क्रेडिट्स पाने के हकदार हो जाते हैं। अभी वैश्विक स्तर पर करीब दो अरब डॉलर का स्वीडिश कार्बन मार्केट है। यह एक खराब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। कार्बन क्रेडिटों का उपयोग ही उन्हें यूरोपीय संघ में निर्यात जारी रखने का पात्र बनाएगा क्योंकि

यूरोपीय संघ उन उत्पादों के आयात पर भी कार्बन टैक्स लगाने का मंत्रय जतला चुका है, जो उसके अपने मानकों से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन से उत्पादित हुए हैं। देशों में पेट्रोल, कोयले जैसे जीवाश्म इंधनों के उत्पादन बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित कार्बन उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता लक्ष्यों को उनके खरीदे कार्बन क्रेडिट्सों के मुआवजे से ही पूरा करने की जरूरत होगी। चिंताजनक है कि अधिकांश देश या उद्यम दुनिया के लक्ष्यों के अनुसार अगले दो-तीन दशकों के भीतर ही कार्बन न्यूट्रल तो होना चाहते हैं किंतु इसे कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म इंधनों के उपयोगों और उत्पादनों को छोड़ते हुए नहीं करना चाहते, बल्कि इसे अन्य किसी को मिली कार्बन क्रेडिट खरीद कर अपने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन की एजब में देकर पूरा करना चाहते हैं। जो प्रतिष्ठान अपने खाते में स्वयं अर्जित या किसी से खरीद कर कार्बन क्रेडिट जोड़ लेते हैं तो उससे वे अपनी कार्यवाहियों के कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं।

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा। -सम्पादक

पुलिस ने की चालानी कार्रवाई के विरोध में भाजपा जिला उपाध्यक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा



14 जनवरी को पतंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन

अम्बिकापुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

विगत वर्ष के भाति इस वर्ष भी पतंग उत्सव का कार्यक्रम गांधी स्टेडियम अम्बिकापुर में 14 जनवरी आयोजित किया गया है सरगुजा सेवा समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस वर्ष भी समिति की तरफ से पतंग उत्सव का कार्यक्रम में फैसी पतंग पतंग काटो प्रतियोगिता रखा गया है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी होंगे प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार रखा गया है प्रथम पुरस्कार 3100 द्वितीय पुरस्कार 2100 तृतीय पुरस्कार एवं फैसी में भी प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार 1100 का व्यवस्था किया गया है समिति के अध्यक्ष श्रीमती रजनी रवि शंकर त्रिपाठी ने अम्बिकापुर की नागरिकों को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील किया है इस इस प्रतियोगिता में समिति के सदस्य उपस्थित होंगे।



मोटर व्हीकल एक्ट के कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज व धक्का-मुक्की

अम्बिकापुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने पर बुलेट चालक ने अपने अन्य साथियों को कार्रवाई स्थल पर बुला लिया। लोगों ने कार्रवाई कर रहे पुलिसकर्मियों को गाली गलौज व धक्का-मुक्की करते हुए बुलेट लेकर भाग गए। यातायात विभाग के सहायक उप निरीक्षक ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार निशिकांत एक्का यातायात शाखा में सहायक

उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। 10 जनवरी को मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई के लिए सहायक उप निरीक्षक की ड्यूटी दरिमा मोड पर लगाई गई थी। इस दौरान दोपहर करीब 2 बजे खरसिया रोड की ओर से बुलेट क्रमांक सीजी 15 सीएफ 2630 का चलाका आया। बुलेट में मडिफाईड सायलेंसर लगे होने पर पुलिस ने रोकर वाहन के कागजात, चालक का ड्रायविंग लायसेंस एव मडिफाईड सायलेंसर लगाने के संबंध में पूछताछ किया गया। पर चालक द्वारा किसी भी प्रकार का वाहन का दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इस स्थिति में पुलिस ने चालानी कार्रवाई करने लगी तो बुलेट चालक ने परिजन को बुलाने की बात कही। कुछ देर बाद दो लोग आए और कार्रवाई कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज व धक्का-मुक्की करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए बुलेट ले गए। एएसआई निशिकांत एक्का ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने बुलेट चालक व अन्य के खिलाफ धारा 132, 221, 296 व 3(5) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

संवाददाता - अम्बिकापुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बलरामपुर कोतवाली के सामने जमीन पर लेटकर पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। शराब के नशे में वाहन चलाने पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। जिन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की वह भाजपा नेता थे। इसकी जानकारी होने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा करना पड़ा और कोतवाली प्रभारी को ट्रांसफर करने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है- 'सुशासन जमीन पर लेटा है'। जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के



कुसमी क्षेत्र के कुछ भाजपा कार्यकर्ता बलरामपुर में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने एक पार्टी में भाग लिया। इसके बाद शनिवार की रात में वापस लौट रहे थे इसी दौरान

पुलिस ने कोतवाली थाना के सामने उन्हें रोक लिया। वाहन चालक व सवार शराब के नशे में पाए गए। नशे की छलात में वाहन चलाने पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर दी।

चलाने के कारण चालान किया है उन्हें तत्काल दोड़ दें। सुशासन कह रहा है कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो थाना प्रभारी 2 दिन में हटा दिया जाएगा।

युवक पर रॉड से बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, घटना का वीडियो वायरल

संवाददाता - अम्बिकापुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े डंडे व रॉड से मारपीट कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसमें जिला बंदर का एक आरोपी अपने साथियों के साथ युवकों के साथ डंडे व रॉड से प्राणाघात हमला करते दिखाई दे रहा है। पीड़ित युवक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार हर्षित चक्रवर्ती पिता मृत्युंजय चक्रवर्ती उम्र 24 वर्ष निवासी सुभाषनगर भगवानपुर का रहने वाला है। वह 10



जनवरी को बाइक से अपने साथी राहुल हलदार, शुभम सरकार के साथ मेडिकल कॉलेज गंगापुर की ओर गया था। इसी बीच तभी विनित बोस, शिवम मिश्रा, आयुष जायसवाल अन्य साथियों के साथ कार व बाइक से आकर गाली गलौज करते हुए रॉड, डंडे और धारदार हथियार से हर्षित चक्रवर्ती के साथ मारपीट करने लगे। जिससे हर्षित को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाना में दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने आरोपी विनित बोस, शिवम मिश्रा, आयुष जायसवाल व अन्य के खिलाफ धारा 115(2), 296,

3(5), 351(3) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।



विवेक दुबे बने शिशु मंदिर संस्थान के संभाग प्रभारी

संवाददाता - अम्बिकापुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

लाइफलाइन अस्पताल के डायरेक्टर व सामाजिक सेवा में सदैव अग्रणी रहने वाले विवेक दुबे को सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग प्रमुख बनाया गया है। संगठनात्मक व्यवस्था के दृष्टिकोण से विवेक दुबे को सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ के संभाग प्रमुख की जिम्मेदारी मिलने पर विवेक दुबे ने कहा है कि सरस्वती शिक्षा संस्थान बच्चों की पढ़ाई के साथ उन्हें नैतिक गुणों से परिपूर्ण बनाता है। संस्थान में अध्ययन करने वाले बच्चे देश के विभिन्न क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। सरगुजा संभाग में शिशु मंदिरों की बेहतर व्यवस्था के लिए वे पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें।

उदयपुर सायर के भूडुमार जंगल में वन विभाग के मिली भगत से दिनदहाड़े अवैध कटाई, आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं



संवाददाता - उदयपुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले के वन परिक्षेत्र उदयपुर अंतर्गत ग्राम सायर के बीट क्रमांक के बीटगाई के मिली भगत से कटाई हो रहा है और कब्जा करने हेतु खुली छूट दिया गया है जिसके कारण सायर का जंगल कटाई कर जंगलों का सफाया किया जा रहा है जिसको देखने वाला इसलिए कोई नहीं है क्योंकि वन विभाग के बीट गाई के मिली

भगत से यह कार्य हो रहा है। जिसको रोकने के लिए ग्राम सायर के निवासियों ने एक लिखित आवेदन वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत कर यह मांग किया है की ग्राम सायर का जंगल में हरे-भरे पेड़ को काटकर घर बाड़ी बना रहे लोगों के ऊपर कार्यवाही करने के संबंध में 9/1/2025 को वन विभाग के वनपरिक्षेत्र अधिकारी को यह अवगत कराया है कि ग्राम सायर के जंगल में दूसरे जगह से आकर शिवगिरी पिता भरोस गिरी

नाम का व्यक्ति घने जंगल में घर बनाकर रह रहा है और लगभग 5 एकड़ जंगल को जमीन को पेड़ों की कटाई कर जमीन कब्जा कर रहा है जिसे बिक्री करने के लिए गिरी के मिली भगत से घुट्टापारा के सीतापुर के अज्ञात व्यक्ति को जंगल के जमीन को लगभग 6 लाख 20000 में बेचने का जानकारी मिल रहा है जिस सायर गांव के हरे-भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जिसे सही समय पर रोकने की

आवश्यकता है वन परिक्षेत्र अधिकारी उदयपुर को निवेदन किया गया है कि दूसरे एरिया के व्यक्ति के द्वारा जंगल को अवैध कटाई किया जा रहा है जिसे तत्काल उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है लेकिन अभी तक इसका कार्रवाई नहीं किया गया है क्या कारण है कि जंगलों का अवैध कटाई करने वालों के ऊपर अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रही है कहीं ना कहीं मिली भगत होने के कारण

ही इस प्रकार से जंगलों का अवैध कटाई किया जा रहा है जिसको रोकने के लिए प्रयास तक नहीं कर रही है। वन विभाग उदयपुर के अधिकारियों को ज्यादातर वन चौकी के कार्यालय में मंडराशती करते हुए देखा जा सकता है लेकिन जंगलों को निगरानी करने के लिए उनको तनिक भी फुर्सत नहीं है। यदि इस विषय को बात करने की कोशिश किया जाए तो ज्यादातर अधिकारी बहाना करते नजर आते हैं।

छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल टीम के लिए मानसी का चयन

संवाददाता - अम्बिकापुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।



सरगुजा जिला बास्केटबॉल टीम में बालिका 17 वर्ग में मानसी सांडिल्य का चयन 68 वीं राष्ट्रीय शालेय क. 1 ड। बास्केटबॉल प्रतियोगिता चेन्नई के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 15 से 19 जनवरी तक आयोजित है। मानसी सांडिल्य सेंट जोन विद्यालय की छात्रा है। मानसी के पिता रुपसाय सिंह नगरपालिका निवासी सफाई सुपरवाइजर हैं। व माता सुमित्रा गृहणी हैं। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि मानसी विगत कई वर्षों से गांधी स्टेडियम के बास्केटबॉल ग्राउंड पर अभ्यास करते आ रही है।

युवा दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन

यातायात पुलिस द्वारा बच्चों को सड़क सुरक्षा का महत्व बताकर यातायात नियमों के पालन किये जाने हेतु किया गया प्रोत्साहित

बच्चों को अपने माता पिता द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं चारपाहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने दी गई समझाईश

संवाददाता - अम्बिकापुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस द्वारा 36 वीं सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत आमनागरिकों को

जागरूक करने लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, इसी क्रम में सरगुजा पुलिस द्वारा अनूठी पहल करते हुए बच्चों को यातायात नियमों के बारे में बताकर परिजनों को बच्चों के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन करने हेतु युवा दिवस के मौके पर यातायात पुलिस एवं पुलिस मितान के संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक को वेलोसिटी एजुकेशन संस्थान के नौनिहालो को चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से सड़क सुरक्षा की थीम पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

सड़क सुरक्षा थीम पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में संस्थान के सभी बच्चों ने बड़ चढ़कर भाग लिए एवं सड़क सुरक्षा के महत्व को अपने



चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, यातायात पुलिस टीम द्वारा बच्चों

को बतलाया गया कि यातायात के नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है, सभी बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता एवं परिजनों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए बोला, बच्चों की बात को परिजनों द्वारा सहर्ष स्वीकार किया जाता है, इसी उद्देश्य से बच्चों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अनूठी पहल शुरू की गई।

कार्यक्रम में पुलिस मितान के सदस्यों द्वारा यातायात के नियमों का महत्व बताकर बच्चों को जागरूक किया गया साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा

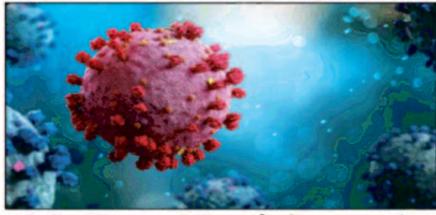


माह के समापन अवसर पर पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जायगा, उक्त कार्यक्रम के आगामी क्रम में दिनांक 16/01/25 को गांधी स्टेडियम अम्बिकापुर में सड़क

सुरक्षा जागरूकता से सम्बंधित रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जायगा, कार्यक्रम के समय की सूचना अलग से जारी की जायगी, कार्यक्रम में 05 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया एवं उपरोक्त प्रतियोगिता में लगभग 40 बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से जागरूकता संदेश भी दिया। सम्पूर्ण कार्यक्रम के यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक तुषि सिंह राजपूत, वेलोसिटी एजुकेशन संस्थान के डायरेक्टर श्री सुमित श्रीवास्तव, अचंता सिन्हा, आरक्षक अमन मानिकपुरी, पुलिस मितान विक्की गुप्ता, श्रुति तिवारी, बसंत श्रीवास्तव, दीपक शर्मा, आर्यन पांडे, श्रेयांश तिवारी सहित यातायात शाखा के पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं संस्थान के शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे।

उत्तरी चीन में घट रही एचएमपीवी संक्रमण की दर, स्वास्थ्य अधिकारी का दावा, दुनिया में वायरस को चिंता

बीजिंग, 12 जनवरी 2025। रविवार को एक चीनी स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि उत्तरी चीन में फ्लू जैसे ह्यूमन मेटाइन्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के संक्रमण की दर घट रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संभावित महामारी को लेकर चिंता है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की तरफ से आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के एक शोधकर्ता वांग लिपिंग ने कहा, ह्यूमन मेटाइन्यूमोवायरस कोई नया वायरस नहीं है, और यह कम से कम कई दशकों से इंसानों के साथ है। वांग ने कहा कि हाल के वर्षों में वायरस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी, जिसका पहली बार 2001 में नीदरलैंड में पता चला था, बेहतर पहचान विधियों के कारण है।



मामलों की दर में गिरावट शुरू हो गई है। हाल के दिनों में उत्तरी चीन में एचएमपीवी संक्रमण में बढ़ोतरी पर चिंताएं सामने आईं, जब अस्पतालों में मास्क पहने रोगियों से भरे होने की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हुईं।

चीन में असामान्य प्रकोप की रिपोर्ट नहीं: WHO
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उसे चीन या अन्य जगहों पर असामान्य प्रकोप की रिपोर्ट नहीं

मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी कोविड-19 से अलग है क्योंकि यह दशकों से मौजूद है और इसके लिए कुछ अंतर्निहित प्रतिरक्षा है। अधिकांश बच्चे 5 वर्ष की आयु तक वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। वांग ने कहा कि वर्तमान में चीन में लोगों को प्रभावित करने वाली सांस संबंधी बीमारियां ज्ञात रोगजनकों के कारण होती हैं, और कोई नई संक्रामक बीमारी सामने नहीं आई है।
एचएमपीवी के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं
स्वास्थ्य आयोग के चिकित्सा

शेख हसीना की भतीजी पर ब्रिटेन में गड़बड़ी के आरोप, मोहम्मद युनूस बोले- जांच जरूरी

ढाका, 12 जनवरी 2025। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद युनूस ने ब्रिटिश मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि ट्यूलिप ने अपनी चाची और पूर्व बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान संपत्तियां हासिल की थीं। एक साक्षात्कार में उन्होंने शेख हसीना के पीएम पद से हटने के बाद भी सिद्दीक और उनके परिवार द्वारा संपत्तियों के इस्तेमाल पर निंदा की। मोहम्मद युनूस ने बांग्लादेश को संपत्तियां लौटाने की मांग की। साक्षात्कार में मोहम्मद युनूस ने कहा, यह एक सीधी छद्मता के बारे में है। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर फर्जी तरीके से धन का गबन करने का आरोप लगाया। - बता दें कि सिद्दीक ब्रिटेन लेबर कबिनेट के सदस्य हैं, जो ट्रेजरी और सिटी मंत्री के आर्थिक सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। साक्षात्कार के अगले ही दिन ब्रिटिश अखबार ने रविवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था-यूके पीएम ने बांग्लादेश पीएम को फटकार के बाद ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करने का आग्रह किया।



विधायक भूलन सिंह मरावी ने पंचायत व नगर पालिका चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया

जनता के समर्थन और मजबूत प्रत्याशियों के वयन से जीत सुनिश्चित करेगी भाजपा

- संवाददाता -
सूरजपुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

पंचायत और नगर पालिका चुनावों की दस्तक के साथ ही स्थानीय विधायक भूलन सिंह मरावी भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वे हर दावेदार पर पानी नजर बनाए हुए हैं और सबसे प्रभावी एवं जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुटे हैं। सर्वे के माध्यम से पंचायत और नगरपालिका में मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा, ताकि हर वार्ड और हर पंचायत में भाजपा की

जीत सुनिश्चित हो सके। विधायक भूलन सिंह मरावी का साफ कहना है कि भाजपा के सता में आने के बाद सरकार ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं और चुनावी वादों को तेजी से पूरा किया है। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा सरकार की नीतियों से संतुष्ट है, और इसी वजह से पंचायत व नगरपालिका चुनावों में भाजपा को अपार जनसमर्थन मिलने वाला है। हमने सरकार बनने के बाद से ही विकास को प्राथमिकता दी है। जनता ने जिस भरोसे के साथ हमें सता सौंपी थी, हम उस पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। अब हमारा लक्ष्य पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने मजबूत रणनीति

तैयार की है और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। विधायक ने बताया कि भाजपा जल्द ही एक चयन समिति गठित करने जा रही है, जिसमें वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। यह समिति नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड पार्षदों और पंचायत चुनावों के प्रत्याशियों का चयन करेगी।



विधायक श्री मरावी ने कहा कि पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। संगठन कार्यकर्ताओं और जनता से बेहतर संवाद रखने वाले नेताओं को तवज्जो मिलेगी।

हरी सब्जियों से भरे वाहन के बीच अंग्रेजी तस्करी, अफसर हैरान, 61 पेट्टी अंग्रेजी, 46 केन बियर जप्त

- संवाददाता -
सरगुजा, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

मध्य प्रदेश से आ रही हरी सब्जियों के बीच शराब की तस्करी भी हो रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के देवसर से हरी सब्जियों से भरे वाहन में शराब और बियर की बोतलें देखकर पुलिस अफसर हक्के-बक्के रहे गए। पुलिस ने सब्जियों के बीच से 61 पेट्टी अंग्रेजी शराब और 46 केन बियर के साथ ही वाहन की जब्त बनाई है। आरोपी भी पुलिस के हथकैदे चढ़ गए हैं। बलरामपुर जिले के वाडफनगर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जप्त की है।



पुलिस ने पिकअप वाहन में छिपाकर ले जाई जा रही 2,928 पाव अंग्रेजी शराब और 46 केन बियर समेत कुल 550.04 लीटर शराब बरामद की। जप्त शराब की कुल कीमत लगभग 4.40 लाख रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी साकिब अहमद (25 वर्ष), निवासी वाडफनगर, को गिरफ्तार कर पिकअप वाहन

(नंबर यू.पी. 64 बी.टी. 7283) भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई 11 जनवरी 2025 को वाडफनगर चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान की। दोपहर करीब 2 बजे वाडफनगर से आ रही पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई। वाहन में सक्की के कैरेट के नीचे शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यह शराब मध्य प्रदेश के सीधी जिले के देवसर से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और सूरजपुर जिलों के ढाबों में सप्लाय करने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को खिलाफ अपराध क्रमांक 00/2025 के तहत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अकित गर्ग और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव बैकर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में नाकाबंदी प्लांट लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस ने यातायात सुरक्षा माह के तहत शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की है। मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 185 के तहत चालान जारी किए जा रहे हैं।

नशे में धुत पटवारी की दबंगई, ग्रामीण से 20 हजार की मांग, नशे में की धक्का-मुक्की

- संवाददाता -
प्रतापपुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

जिले के ग्राम गोविंदपुर में पदस्थ पटवारी मोगेंद्र सिंह का शराब के नशे में ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पटवारी ने ऋण पुस्तिका देने के एवज में 20 हजार रुपए की मांग की और पैसा न देने पर ग्रामीणों को कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मामले की शिकायत पॉइंट ग्रामीण रोहित रजक ने रैवटी चौकी में की है।



वया है पूरा मामला?
शुक्रवार की शाम ग्राम गोविंदपुर निवासी रोहित रजक अपने साथी के साथ पटवारी कार्यालय में ऋण पुस्तिका लेने पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी मोगेंद्र सिंह शराब के नशे में थे और उन्होंने ऋण पुस्तिका के बदले 20 हजार रुपए की मांग की। पैसे देने से मना करने पर पटवारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया।

पटवारी कार्यालय बना नशाखोरी और दलाली का अड्डा
ग्रामीणों ने बताया कि गोविंदपुर पटवारी कार्यालय में शाम होते ही शराबखोरी और गैरकानूनी गतिविधियां आम हो चुकी हैं। पटवारी मोगेंद्र सिंह अक्सर अपने साथ एक दलाल रखता है, जो ग्रामीणों से फौती, नामांतरण, नक्शा दुरुस्त करने और अन्य दस्तावेजों के लिए

रिश्तव मांगता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी बिना पैसे कोई भी सरकारी काम नहीं करता।
ग्रामीणों ने उठाई कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पटवारी मोगेंद्र सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भ्रष्टाचार व नशाखोरी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

चक्कर लगाना पड़ता है। यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पूर्व भी दर्जनों ऐसे मामला सामने आ चुके हैं जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। वही अधिकारी जांच के नाम पर खाना पूर्ण कर खुलेआम भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास करते हैं जिससे ऐसे लोगों के हिसले बुलंद है।
पुलिस जांच में जुटी

रैवटी चौकी प्रभारी ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में रैवटी चौकी प्रभारी ने कहा कि मामले की शिकायत हुई है जांच की जा रही है। तथा उच्च अधिकारियों की दिशा निर्देश पर जांच कर कार्यवाही जाएगी। एसडीएम ललिता भगत ने कहा कि मामला के गंभीरता को देखते हुए जांच कराई जाएगी दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी।



नगर पंचायत लखनपुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 1100 आवास पूर्ण कर नयी उपलब्धि हासिल की...

- संवाददाता -
लखनपुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत शासन के निर्देशानुसार रैपिड असेसमेंट सर्वेक्षण मांग सर्वेक्षण हेतु नगर पंचायत कार्यालय में शिफ्ट का आयोजन किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में वंचित हितग्राहियों को, अब दूसरे चरण में मकान उपलब्ध कराने हेतु आवेदन संबंधी जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत इच्छुक हितग्राही केन्द्र सरकार के पोर्टल पर स्वयं भी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही नगर पंचायत कार्यालय में आकर आवेदन जमा भी करा सकते हैं। 1100 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराने पर नगरवासियों के द्वारा स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल एवं अध्यक्ष श्रीमती सावित्री दिनेश साहू एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी विधासागर चौधरी का आभार व्यक्त किया गया है।



अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं ने किया श्रमदान

पंचायत ने स्वच्छता किट वितरित कर डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण पृथक्करण कार्य की शुरुआत

- संवाददाता -
सूरजपुर, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

कलेक्टर डी. राहुल केंद्रेट के दिशानिर्देशन पर सरगुजा निदेशक

के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत पिपरिया में युवाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों स्वच्छताग्रहियों स्व सहायता समूह के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करने हेतु अपील गई। ग्राम पंचायत के माध्यम से नियमित रूप से डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण हेतु स्वच्छताग्रहियों को स्वच्छता किट

प्रदान की गई एवं व्यवसायिक संस्थानों स्कूल आंगनबाड़ियों हेतु उस्टबिन वितरण कर सोर्स सेग्रीगेशन हेतु अपील की गई।

घर से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे के उचित प्रबंधन, घरेलू गंदे पानी के प्रबंधन हेतु किचन गार्डन निर्माण एवं उपयोगिता हेतु जागरूक किया गया। उक्त आयोजन में जिला समन्वयक राजेश जैन, सरपंच श्री मति ललिता बाई, सचिव विक्रम, ब्लॉक समन्वयक प्रभा पयासी, मुकेश कुमार के साथ बड़ी संख्या में युवा स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रदान की गईं।



में, कक्षा दौड़ का आयोजन किया गया और आउटडोर खेल में बालिका और बालक वर्ग के लिए क्रिकेट, खो खो कबड्डी, वॉलीबॉल, तवा फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक, एथलीट के रूप में 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर का बालक वर्ग के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। सभी खेलों में विद्यार्थियों ने बहुरूपता का भागीदारी दिया। बच्चों को यह गेम बहुत ही पसंद आया। खास तौर पर रस्साकशी का खेल जिसमें शक्ति का प्रदर्शन किया गया

किसके अनुमति से काटा सूरजपुर रेवती रमण कॉलेज परिसर में लगा यूकेलिप्टस का पेड़ ?



- ▶ पेड़ काटने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं...व्या परिवहन करने के लिए भी दस्तावेज की जरूरत नहीं ?
- ▶ यूकेलिप्टस तस्कर कई शासकीय जमीन पर लगे पेड़ों को भी ले जा रहे हैं काटकर
- ▶ सूरजपुर जिले से कट रहे हैं यूकेलिप्टस के पेड़ कोरिया जिले में बने गोदाम तक पहुंच रहे...
- ▶ यूकेलिप्टस पेड़ काटने के मामले में कुछ भाजपा नेता भी शामिल हुए...
- ▶ यूपी से आए लकड़ी माफिया स्थानीय स्तर के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे बड़े पैमाने पेड़ काटने का काम



लैंड से लेकर शासकीय जमीन पर कई जगह पर पेड़ लगे हुए थे, यदि इस पेड़ की बिक्री हुई है तो नियम से दस्तावेज बनाकर उस पेड़ की कीमत की नीलामी होनी थी और नीलामी से उसे पैसे को राजस्व के खाते में जमा होना था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जबकि राजस्व से लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से इन सब बातों से नजर अंदाज किया है।

जिम्मेदार कुछ भी कहने से बच रहे

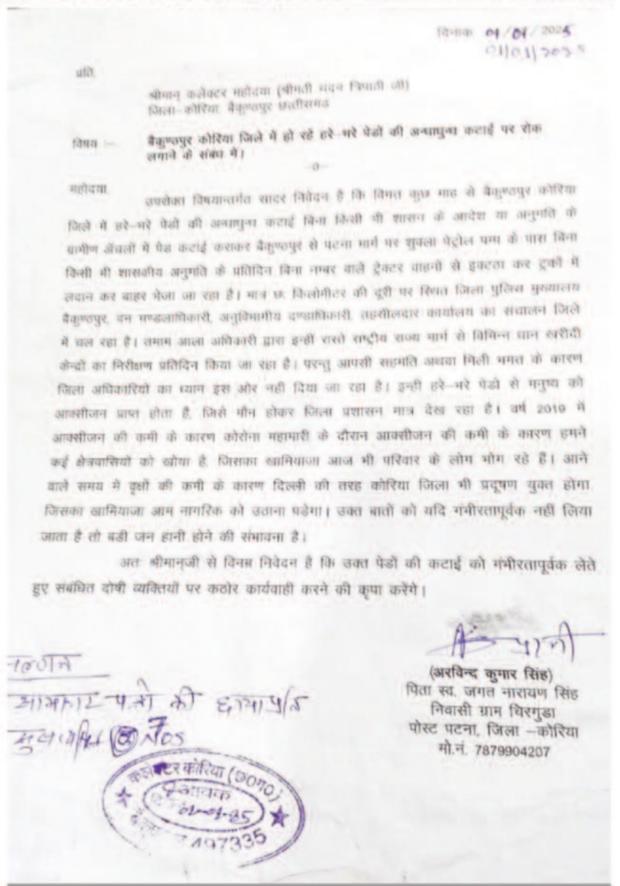
रेवती रमण कॉलेज के प्रिंसिपल से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि वन विभाग से उन्होंने परमिशन लाया था अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वन विभाग से परमिशन किसने दिया? और यदि वन विभाग ने उन्हें काटने का परमिशन दिया या फिर वन विभाग ने पेड़ बेचा तब तब तक सवाल उसे पर खड़े होते हैं पर इसकी पूछ परख कौन करेगा जिसके पास इसका अधिकार है? वह तो मुख्य दर्शन बना बैठा है।

बिना दस्तावेज दौड़ रहे वाहन से दुर्घटना का खतरा

एक तरफ जिले में सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आए लकड़ी तस्कर बिना दस्तावेज का पेड़ मिला गाड़ी से सुबह से शाम तक लकड़ी खेह रहे हैं जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है वह दूसरी तरफ बिना दस्तावेज का मुसाफिर भी नहीं चेक किया जा रहा है, बाहर के व्यक्ति कहीं कोई बड़े वारदात को इसी बीच अंजाम न दे दें और प्रशासन हथ पैर हथ धरे बैठें में रह जाए।

आपदा में अवरस की तरह यूकेलिप्टस पेड़ की हो रही काटने?

यूकेलिप्टस पेड़ की काटने आपदा में अवरस जैसी हो गई है क्योंकि जब से यह बात पता चली है कि यूकेलिप्टस का पेड़ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर इस पेड़ की कीमत आज भी है जो इसे दूसरे राज्यों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, और कमाई के लिए ही इस समय सूरजपुर जिले में यूकेलिप्टस के पेड़ की काटने की तस्करों द्वारा की जा रही है, बस उनके लिए यह बात आसान हो गया है की काटने में कोई प्रतिबंध नहीं है, पर शायद उन्हें यह नहीं पता है कि बेचेने के बाद लैंड जाने के लिए अनुमति होनी आवश्यक है, इस लकड़ी की तस्करों में कहीं ना कहीं शासन भी तस्करों के साथ है, क्योंकि जिस प्रकार से इस लकड़ी की काटने तस्कर अपने मुनाफा के लिए कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा पा रहे हैं, यही वजह है कि दूसरे राज्यों से बुलाकर लकड़ी काटने व बेचने वाले ले जाने वाले को लकड़ी माफिया ने टेंडर दे रखा है। पर मुनाफा तस्कर कमा रहे हैं नुकसान जिले का हो रहा है यहाँ तक की पेड़ लगाकर बड़े करने वाले को भी इसका भारी भ्रकम नुकसान हो रहा है, निजी जमीनों के पेड़ तो काटे ही जा रहे हैं जो पेड़ सरकारी खर्च पर लगाए गए थे उन पेड़ों को भी निशुल्क काटकर



लकड़ी माफिया अपना जेब भर रहे हैं। पर्यावरण के लिए नुकसान पर यूकेलिप्टस का पेड़ तस्करों के लिए मुनाफे वाला

यूकेलिप्टस का पेड़ पर्यावरण खासकर भू जल स्रोत के लिए सही नहीं माना जाता। यूकेलिप्टस का पेड़ भू जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाता है यह सही भी है लेकिन यूकेलिप्टस का पेड़ फिर भी बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। कोरिया जिले सहित सूरजपुर जिले में काफी तादाद में यह वृक्ष लगा हुआ था जो अब लकड़ी तस्करों के लिए मुनाफे का कारण बन रहा है। अब लकड़ी तस्कर जो बाहरी हैं वह खुलेआम इसको काट रहे हैं और अन्य राज्यों को भेज रहे हैं।

अरविन्द सिंह ने कलेक्टर कोरिया से शिकायत कर कहा की विगत कुछ माह से जिले में हरे-भरे पेड़ों की अन्धाधुंध काटने बिना किसी भी शासन के आदेश या अनुमति के ग्रामीण अंचलों में पेड़ काटने करारक बैकूणपुर से पटना मार्ग पर शुक्ला पेट्रोल पम्प के पास बिना किसी

भी शासकीय अनुमति के प्रतिदिन बिना नम्बर वाले ट्रेक्टर वाहनों से इकट्ठा कर टुकों में लदान कर बाहर भेजा जा रहा है। मात्र छः किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिला पुलिस मुख्यालय बैकूणपुर, वन मण्डलाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार कार्यालय का संचालन जिले में चल रहा है। तमाम आला अधिकारियों के दौरान आक्सोजन की कमी के कारण कोरिया जिला भी प्रदूषण युक्त होगा जिसका खामियाजा आम नागरिक को उठाना पड़ेगा। उक्त बातों को यदि गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है तो बड़ी जन हानी होने की संभावना है।

अरविन्द सिंह ने कलेक्टर कोरिया से शिकायत कर कहा की विगत कुछ माह से जिले में हरे-भरे पेड़ों की अन्धाधुंध काटने बिना किसी भी शासन के आदेश या अनुमति के ग्रामीण अंचलों में पेड़ काटने करारक बैकूणपुर से पटना मार्ग पर शुक्ला पेट्रोल पम्प के पास बिना किसी

आम सूचना

ग्राम पंचायत - मलकडोल दिनांक - 22/10/2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देववती गोड पति धर्मपाल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मलकडोल तहसील भरतपुर जिला एम.सी.बी. छग. ग्राम पंचायत मलकडोल का सरपंच है जो कि ग्राम पंचायत मलकडोल की निर्वाचित वर्तमान सरपंच है। यह कि ग्राम पंचायत मलकडोल एवं जे.पी. एसोसिएट्स फ.न. 03 क्वालिटी परिक्रमा प्रेस काम्प्लेक्स जे.पी. एस. नगर तह. हुजूर भोपाल म.प्र. पाटनर पुष्पेन्द्र सिंह गहरवार पिता श्री कौशल प्रताप सिंह गहरवार उम्र 46 वर्ष निवासी मकान नं. 309 वार्ड नं. 09 सुन्दर नगर आर्डीया टावर बोदा बाग हुजूर जिला रीवा म.प्र. के मध्य अनुबंध किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत मलकडोल के पारित प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 22.10.2024 द्वारा ओदारी नदी के ख.न. 53 रकबा चार हेक्टर स्वीकृत खदान का अनुबंध को दिनांक 22/10/2024 को निरस्त कर दिया गया है। यह कि उक्त अनुबंध पत्र को निरस्त करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत है जो सत्य एवं सही है।
सरपंच के द्वारा सत्यापन किया गया है जिसमें स्वयं ग्राम पंचायत मलकडोल की सरपंच देववती गोड पति धर्मपाल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मलकडोल तहसील भरतपुर जिला एम.सी.बी. छग. ने सत्यापित करते हुए कहा है कि शपथ पत्र के खण्ड क्रमांक 01 से 03 तक भरे निजी जानकारी के अनुसार लेख किया गया है जो सही एवं सत्य है।
सत्यापनकर्ता
देववती गोड पति धर्मपाल
सरपंच - ग्राम पंचायत मलकडोल
निवासी ग्राम मलकडोल
तहसील भरतपुर जिला एम.सी.बी. छग.

-शमरोज खान- सूरजपुर/कोरिया 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।

वर्तमान में जैसी प्रशासन की स्थिति है उसे देखकर लग रहा है कि वाकई में प्रशासन अंधा, गुंगा व बहरा बना बैठा है, निरंकुश की स्थिति बनी हुई है यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी से आए लकड़ी माफिया स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर बड़े स्तर पर यूकेलिप्टस पेड़ की काटने कर रहे हैं, कोरिया सूरजपुर में यूकेलिप्टस पेड़ की अंधाधुंध काटने हो रही है, भारत सरकार द्वारा पेड़ को काटने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है अब यह बात कितनी सही है ये तो भारत सरकार जाने और स्थानीय प्रशासन? पर वहीं जानकारों का मानना है कि हरे पेड़ काटने के लिए कौन से पेड़ काटने की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। सवाल तो यह भी है कि निजी स्थान के तो पेड़ काटे जा रही हैं, पर समझ में यह नहीं आ रहा की शासकीय जमीनों पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काट कर लकड़ी माफिया ले गए, पर क्या इस पेड़ को काटने की अनुमति ली गई थी? क्या यह पेड़ कॉलेज के प्रिंसिपल की निजी थी और यदि यह पेड़ कटी या बिकी तो क्या यह पैसे शासन के राजस्व जमा हुआ? क्या यह गलत नहीं है या फिर यह सब देखकर भी प्रशासन अनजान है?

जात होकी नीलगिरी या यूकेलिप्टस के पेड़ पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि यह पेड़ 18-20 गुना वाष्पोत्सर्जन करता है इससे सूखा पड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है, साथ ही इसके पोशाक जहरीले होने की वजह से मिट्टी के पोषक तत्व को खींचकर बंजर बना देती है जिस वजह से इस पेड़ को पर्यावरण के हिसाब से हानिकारक माना जाता है यही वजह है कि इस पेड़ की काटने पर कोई भी रोक नहीं है, पर यदि रोक है तो वह रोक है अपने पेड़ों की काटने के लिए अनुमति लेने

की, यह अनुमति इसलिए ली जाती है क्योंकि पेड़ को बेचने में आसानी हो सके, पेड़ की काटने के लिए अनुमति जरूरी नहीं है पर पेड़ को बेचने के लिए अनुमति होती है, इस समय सूरजपुर जिले के हर गांव तक यूकेलिप्टस पेड़ की अंधाधुंध काटने हो रही है और यह पेड़ दूसरे राज्यों में तस्करों द्वारा भेजे जा रहे हैं, यदि कहा जाए तो आने पीने रेट में तस्कर इस पेड़ को काटकर अच्छे दामों पर बाहर बेच रहे हैं, निजी जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ तो काटे जा ही रहे हैं, साथ ही शासकीय जमीन पर भी लगे यूकेलिप्टस के पेड़ को काटकर तस्कर बेच दे रहे हैं, पर सवाल यह उठता है कि क्या यूको लिप्टस जो शासकीय जमीन पर लगे हुए हैं जिसे लगाने के लिए शासन ने काफी पैसे खर्च किए हैं उस पेड़ को भी वह फ्री में काट कर ले जा रहे हैं, जबकि वह पेड़ अच्छे दामों पर बाहर बेचे जा रहे हैं क्या उस पेड़ की काटने का पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाना चाहिए? क्या यह नियम विरुद्ध तरीके से तस्करों नहीं जाना जाएगा?

दूसरे राज्य से आए लोग कर रहे पेड़ की काटने

दूसरे राज्यों से आए लोग यूकेलिप्टस पेड़ की काटने में शामिल है, यूकेलिप्टस पेड़ के काटने के अड़ा में कई पेड़ काटे जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं है, मनचाहा पेड़ की काटने कर रहे हैं परिवहन में भी इन्हें कोई रोक-टोक नहीं हो रहा, नाहीं कोई दस्तावेज चेक कर रहे हैं सूत्रों का कहना है कि इस पेड़ के अवैध काटने मामले में स्थानीय भाजपा नेता भी शामिल है।

दर्जनों बिना नंबर प्लेट व दस्तावेज वाली गाड़ियां दौड़ रहे हैं पेट काटने में...बिना नियम कायदों की डाला बाँड़ी वाली ट्रेक्टरों से हो रहा लकड़ियों का परिवहन, कौन करेगा कार्यवाही?

सूत्रों का कहना है कि पेड़ काटने के लिए आए

बाहरी लोग दर्जनों बिना नंबर प्लेट एवं बिना दस्तावेज वाली गाड़ियां लेकर पूरे जिले में दौड़ रहे हैं और जहाँ यूकेलिप्टस का पेड़ मिला रहा है वहाँ काट रहे हैं और कटी हुई पेड़ को सूरजपुर के पड़ोसी जिला कोरिया के बैकूणपुर में दो जगह इकट्ठा किया जा रहा है, अब यह गोदाम का रूप ले चुका है और वहाँ से ट्रक के माध्यम से अन्य राज्यों में जा रहा है और सवाल यह है कि ना काटने की परमिशन न परिवहन के लिए दस्तावेज फिर भी किस रसूखदार के इशारे पर पूरा काम हो रहा है। लकड़ियों का परिवहन जिन ट्रेक्टरों से हो रहा है वह अन्य राज्यों की ट्रेक्टर हैं। ट्रेक्टरों में न तो इंजन का नम्बर है न ही डाला बाँड़ी का नंबर है। डाला बाँड़ी का बनावट भी नियम कायदों के विपरीत है जो शायद परिवहन और यातायात विभाग के लिए कार्यवाही का कारण बनना चाहिए। क्षेत्र के जिले के वाहनों पर कार्यवाही करने वाले यातायात विभाग परिवहन विभाग के कर्मचारियों की निगाह इन ट्रेक्टरों पर क्यों नहीं पड़ रही है यह भी सवाल है। इन ट्रेक्टरों पर कौन कार्यवाही करेगा ओवरलॉड पर कौन एक्शन लेगा और कौन इनके कागज की जांच करेगा यह भी प्रश्न है। इन ट्रेक्टरों की गति और भार खेने की क्षमता कितनी होनी चाहिए और कितनी खेकर यह ला ले जा रहे हैं इसकी जांच कौन करेगा यह भी देखने वाली बात होगी।

शासकीय जमीन पर प्लांटिंग वाले यूकेलिप्टस भी कट कर चले गए अन्य राज्य

यूकेलिप्टस के पेड़ सिर्फ निजी जमीनों पर ही नहीं थे कई शासकीय जमीनों पर भी कई जगह पर लाखों यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए थे, इस यूकेलिप्टस के पेड़ की काटने भी हो गई और यह पेड़ छत्तीसगढ़ के बाहर चले गए, अब सवाल यह उठता है कि शासकीय पेड़ों की काटने की अनुमति किसने दी और यदि काटने की अनुमति दी तो आखिर उसे पेड़ को किसने लगवा क्या उसने उसे राजस्व को शासन के खाते में जमा किया? फरिस्ट

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सफाई कर्मियों स्वच्छता दीदियों के लिए विशेष शिविर

▶ नगर की जनता इस योजना की जमकर कर रही हैं सराहना...प्रदेश के मुख्यमंत्री का किया आभार सफाई कर्मचारियों को इस शिविर से मिल रहा है विशेष लाभ

- संवाददाता - एमसीबी, 12 जनवरी 2025 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्र के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत चिरमिरी

नगर निगम क्षेत्र के वाई क्रमांक - 27 गोदरीपारा हनुमान मंदिर के पास विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेष रूप से स्वच्छता कर्मियों नगर में डोर डोर कार्यरत स्वच्छता दीदियों का विशेष रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निरःशुल्क दवा वितरण किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत



वर्तमान में नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट की 02 वाहन संचालित हैं जिसमें शासन के द्वारा उपलब्ध मोबाइल मेडिकल यूनिट में 01 एम.बी.बी.एस.डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ए.एन.एम. एवं वाहन चालक रहते हैं जिसमें 41 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क

कराए जाते हैं वहीं डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया जाता है, मोबाइल मेडिकल यूनिट में मरीजों का रिकॉर्ड ऑनलाइन एंटी किया जाता है और चिकित्सक के द्वारा गंभीर मरीजों को शासकीय अस्पतालों एवं सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया जाता है। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में देखा जाए तो उक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में 2298 शिविरों का आयोजन कर 155782 मरीज का इलाज किया जा चुका है तथा 38281 मरीज का लैब टेस्ट किया जाकर 137046 मरीज को दवा वितरण किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उक्त योजना के संचालन से गरीब तबके के लोगों में खुशी है, और उन्हें निरःशुल्क दवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस शिविर में न केवल सफाई कर्मियों वह स्वच्छता दीदियों की

स्वास्थ्य की जांच की गई बल्कि फिटनेस के लिए उन्हें विशेष रूप से तक भी लगाए गए।
वही आयुक्त राम प्रसाद आचला ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शिविर से नगर में आमनागरिकों का निरःशुल्क इलाज कर उन्हें निरःशुल्क दवा का वितरण किया जाता है साथ ही समय-समय पर स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मियों स्वच्छता दीदियों का विशेष रूप से स्वास्थ्य का परीक्षण भी करा रहे हैं जिससे कर्मचारियों को अच्छे स्वास्थ्य वातावरण निर्मित किया जा सके।

14 वर्षीय इरा जाधव ने अंडर-19 महिला 50 ओवर के मैच में 346 रन बनाकर इतिहास रच दिया

अलूर, 12 जनवरी 2025। मुंबई की 14 वर्षीय इरा जाधव ने 157 गेंदों पर 42 चौकों और 16 छकों की मदद से नाबाद 346 रन बनाकर इतिहास रच दिया। यह महिला अंडर-19 वन डे टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। रविवार को अलूर क्रिकेट ग्राउंड पर मेघालय के खिलाफ खेलते हुए इस किशोरी ने 220.38 की स्ट्राइक रेट से गेंद को हिट किया। जाधव ने स्मृति मंधाना के आयु वर्ग के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, क्योंकि वह बीबीसीआई द्वारा आयोजित किसी भी सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में तिहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय (पुरुष या महिला) बन गई हैं। उनके तिहरे शतक ने मुंबई को 50 ओवरों में 563/3 का विशाल स्कोर बनाने में मदद की - जो सभी टूर्नामेंटों और आयु समूहों में किसी भारतीय महिला घरेलू टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है।

धाकड़ बॉलर की बादशाहत होगी खत्म

20आई क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा करिश्मा

नई दिल्ली, 12 जनवरी 2025। नए साल का आगाज हो चुका है और टीम इंडिया अपने घर में इस साल की पहली सीरीज खेलने जा रही है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी 20आई सीरीज खेलेगी जिसका आगाज 22 जनवरी से कोलकाता में होगा। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम में 14 महीने बाद मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। शमी ने साल 2023 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच खेला था। इसके बाद उनके टखने की सर्जरी हुई थी और तब से ही वह टीम इंडिया में वापसी की राह देख रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच टी 20आई सीरीज में कुल 5 मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्ताना सुप्रिया सुनील यादव के हाथों में होगी जबकि अक्षर पटेल उपकप्तान की भूमिका में होंगे। इस सीरीज में वैसे तो कई भारतीय खिलाड़ियों पर नजर रहेगी लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद अर्शदीप सिंह से होगी जो 2022 में डेब्यू



के बाद से टीम इंडिया के लिए लगातार टी 20आई क्रिकेट खेल रहे हैं और अब टीम के प्रमुख गेंदबाज बन चुके हैं। पिछले 30 महीनों में अर्शदीप सिंह 60 टी 20आई मैच खेल चुके हैं और 18.10 के औसत से 95 विकेट अपने नाम किए हैं। अर्शदीप के पास अब इंग्लैंड के खिलाफ टी 20आई सीरीज में कीर्तिमान रचने का शानदार मौका है।

अर्शदीप के नाम होगा बड़ा करिश्मा

दरअसल, अर्शदीप सिंह 2 विकेट लेते ही युजवेंद्र चहल की टी 20आई क्रिकेट में डेढ़ साल से चली आ रही बादशाहत खत्म कर देंगे। चहल भारत के लिए टी 20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट अपने

नाम किए हैं। चहल के इस आंकड़े को पीछे छोड़ने के लिए अर्शदीप को सिर्फ 2 विकेट लेने की दरकार है। यही नहीं, अगर अर्शदीप इस सीरीज में कुल 5 विकेट ले लेते हैं, तो वह टी 20आई क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। अब तक कोई भी भारतीय गेंदबाज इस ऐतिहासिक आंकड़े को नहीं छू सका है। ऐसे में

अर्शदीप के पास इस मुकाम पर पहुंचने का शानदार मौका होगा। भारत के लिए टी 20 आई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर

युजवेंद्र चहल - 96 विकेट
अर्शदीप सिंह - 95 विकेट
भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट
जसप्रीत बुभराह - 89 विकेट
हार्दिक पांड्या - 89 विकेट
अगर अर्शदीप इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो वह टी 20आई क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के 9वें तेज गेंदबाज बन जाएंगे। अर्शदीप अगर सीरीज के पहले 2 मैचों में ही 5 विकेट झटक लेते हैं, तो वह टी 20आई में सबसे तेज विकेट का सैकड़ा पूरा करने वाले अर्शदीप दुनिया के तीसरे गेंदबाज और पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे।

टी 20आई क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज
राशिद खान (स्मिटर) - 53
संदीप लामिछाने (स्मिटर) - 54
वानिंदु हसरंगा (स्मिटर) - 63 मैच
हारिस रऊफ (पेसर) - 71 मैच

स्मृति मंधाना ने फिफ्टी लगाते ही किया बड़ा कारनामा

तोड़ा अंजुम चोपड़ा का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 12 जनवरी 2025। भारतीय महिला टीम अभी घर पर आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मुकामले को उन्होंने 6 विकेट से अपने नाम किया तो वहीं दूसरे मैच में भी अब तक टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार देखने को मिला है। इस सीरीज में हरमनप्रीत कौर की अनुपस्थिति में भारतीय महिला टीम की कप्तानी कर रही ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना का अब तक इस सीरीज में बल्ले से काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें पहले मुकामले में जहां उन्होंने 41 रनों की पारी खेली थी तो वहीं दूसरे मुकामले में उनके बल्ले से 73 रनों की बेहतरीन पारी देखने को मिली, जिसके दम पर उन्होंने एक बड़ा कारनामा भी करने में कामयाब हुई।



स्मृति मंधाना ने तोड़ा अंजुम चोपड़ा का रिकॉर्ड

महिला वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से अब तक सबसे ज्यादा अलग-अलग देशों के खिलाफ 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम पर है जिन्होंने वनडे में 10 महिला टीमों के खिलाफ ये कारनामा किया है, वहीं इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर स्मृति मंधाना का नाम है जो आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ अंजुम चोपड़ा को पीछे छोड़ने में कामयाब हुई। स्मृति ने अपने वनडे

अलग देशों के खिलाफ 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम पर है जिन्होंने वनडे में 10 महिला टीमों के खिलाफ ये कारनामा किया है, वहीं इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर स्मृति मंधाना का नाम है जो आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ अंजुम चोपड़ा को पीछे छोड़ने में कामयाब हुई। स्मृति ने अपने वनडे

भारत के लिए महिला वनडे में सबसे ज्यादा अलग-अलग देशों के खिलाफ 50 प्लस रनों की पारी खेलने वाली खिलाड़ी

मिताली राज	- 10
स्मृति मंधाना	- 9
अंजुम चोपड़ा	- 8
हरमनप्रीत कौर	- 7
जया शर्मा	- 7

वनडे में स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस रनों की पारियां

स्मृति मंधाना ने अब तक अपने वनडे करियर में इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस रनों की पारियां खेली हैं, जिसमें उनके बल्ले से 8 पारियां 50 से अधिक रनों की देखने को मिली हैं। इसके बाद मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ 5, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-4 पारियां जबकि न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-3 पारियां। वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ 1-1 बार 50 प्लस रनों की पारी खेली है।

करियर में 9वें देश के खिलाफ 50 प्लस रनों की पारी खेली है।



चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश ने किया टीम का ऐलान

दिग्गज ऑलराउंडर बाहर

ढाका, 12 जनवरी 2025। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख नजदीक आ रही है और धीरे-धीरे सभी देशों ने अपनी-अपनी टीम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद अब बांग्लादेश ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश ने अपनी टीम का कप्तान नजमुल हसन शांतो को बनाया है। अनुभवी तेज गेंदबाज मुश्फिकुर रहम और महमूदुल्लाह टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन स्टर ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को टीम में शामिल नहीं किया गया है। शाकिब अल हसन का कारण बैन झेल रहे हैं। शाकिब के अलावा लिटन दास को भी टीम में जगह नहीं मिली है।

शाकिब दूसरे टेस्ट में भी हुए फेल

बांग्लादेश के स्टर ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करारा झटका लगा जब वह अपने गेंदबाजी एक्शन के दूसरे टेस्ट में फेल रहे जिसके बाद उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया। शाकिब इससे पहले ब्रिटेन में ट्वेंटी 20 टूर्नामेंट में स्टर ऑलराउंडर यूनियर्सिटी में

अपने बॉलिंग एक्शन के स्वतंत्र मूल्यांकन में फेल रहे थे। इसके बाद इस स्मिटर को गेंदबाजी करने से रोक दिया गया था। उनके एक्शन की 15 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट की गई थी। पिछले महीने चेन्नई स्थित श्री रामचंद्र सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस में इस ऑलराउंडर का दोबारा टेस्ट किया गया, लेकिन नतीजों से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।

एक ही ग्रुप में बांग्लादेश और भारत

बांग्लादेश की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस रूप में न्यूजीलैंड की टीम भी शामिल है। बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करेगी। ये मुकामला 20 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए ये मुकामला काफी अहम होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश की टीम इस प्रकार है- नजमुल हसन शांतो (कप्तान), सोम्या सरकार, तंजीद हसन, तौहीद हदोय, मुश्फिकुर रहम, एमडी महमूद उल्लाह, जेकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसेन, तस्कीन अहमद, मुस्ताफिजुर, परवेज हुसेन इमोन, नसुम अहमद, तंजीद हसन शाकिब, नाहिद राणा।

खतरे में 24 साल के पाकिस्तान के धाकड़ खिलाड़ी का टेस्ट करियर

इस्लामाबाद, 12 जनवरी 2025। एक वक्त था जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को भविष्य का बसीम अक़रम और वकार यूनस जैसा तेज गेंदबाज बताया जा रहा था लेकिन वक्त बदला और सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गईं। 24 साल का ये तेज गेंदबाज अब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ महीनों से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में अब तेज गेंदबाज का टेस्ट करियर खतरे में

पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल, पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को वेस्टइंडीज के खिलाफ



घरेलू मैदान पर होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया है जिससे उनका टेस्ट क्रिकेट में भविष्य संकट में पड़ गया है। कयास लगाए जाने लगे हैं

कि अब शाहीन की टेस्ट टीम में वापसी मुश्किल है। शाहीन को 2024 की शुरुआत से पाकिस्तान के आखिरी 12 टेस्ट मैचों में से आठ मैच से या तो बाहर कर दिया गया या फिर उन्हें आराम दे दिया गया। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसकी धरती पर खेले गए दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था। तब सिलेक्टर्स ने सफाई देते हुए कहा था वे उन्हें 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना चाहते हैं।

हिसाब बराबर से आर माधवन की पहली झलक आई सामने



रिलीज तारीख से भी उठा पर्दा

अभिनेता आर माधवन को पिछली बार फिल्म शैतान में देखा गया था, जिसमें उनकी अदाकारी की खूब तारीफ हुई। 65 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने भारत में 211 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बहुरहाल, माधवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म हिसाब बराबर को लेकर चर्चा में हैं। अब फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठा गया है। हिसाब बराबर से माधवन की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। माधवन की फिल्म हिसाब बराबर सिनेमाघर में नहीं, बल्कि ओटीटी पर रिलीज होगी। इस फिल्म का प्रीमियर 24 जनवरी, 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो 5 पर होने जा रहा है। इस फिल्म को आप हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, जब एक आम आदमी उठता है तो सिस्टम हिल जाता है। जालसाज सावधान। अब माधवन करीब हिसाब बराबर इस फिल्म के निर्देशन की कप्तान अश्विनी धीरे ने संभाली है। हिसाब बराबर में आर माधवन और कर्ति कुल्हारी के अलावा अनिल पांडे, महेंद्र राजपुर, फैजल राशिद, बॉन्डप शर्मा और रश्मि देसाई भी हैं। अश्विनी धीरे ने इसका डायरेक्शन किया है, जबकि ज्योति देशपांडे, शरद पटेल और श्रेयाशी पटेल ने इसे प्रोड्यूस किया है।

सोनिया बंसल 2025 के लिए बेहद उत्साहित हैं

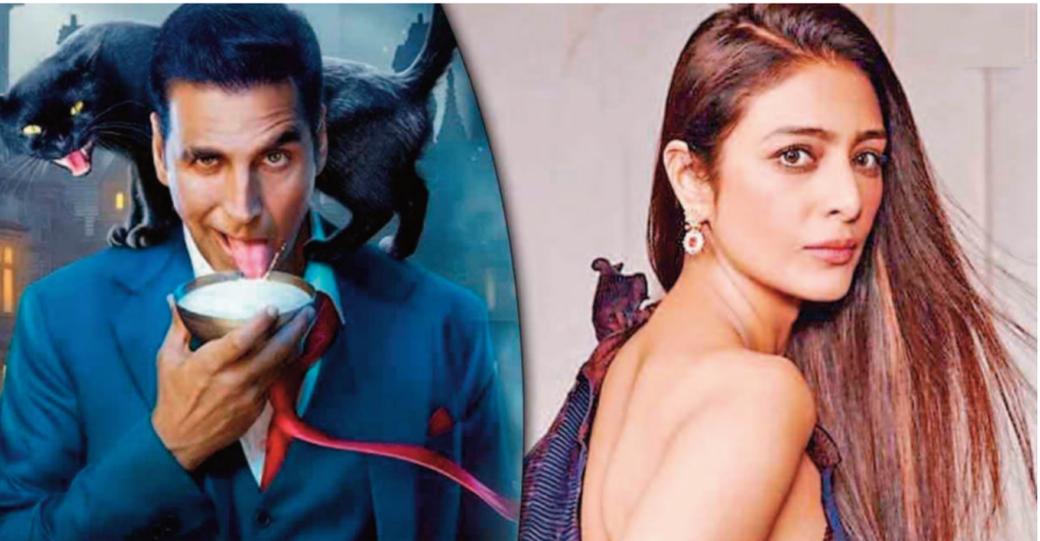
बिग बॉस सीजन 17 की फेम सोनिया बंसल ने आगरा से बॉलीवुड और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तक का एक पेशाने त सफर तय किया है। वह नए साल में और भी कई उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब धावी में दृढ़त्व में भाग लेने से पहले, सोनिया डिप्रेशन से अपनी लड़ाई के लिए चर्चा में थीं, लेकिन अब उन्होंने कड़ी मेहनत, खुशी और अपने काम के प्रति प्रियार के साथ डिप्रेशन से बाहर निकलने का कारण ढूंढ लिया है। फिलहाल, मैंने बॉलीवुड और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दोनों में कई रोमांचक प्रोजेक्ट साइन किए हैं। मैं दोनों इंडस्ट्री की रचनात्मकता और मेरे जैसे महत्वाकांक्षी



कलाकारों को मिलने वाले अवसरों के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। मैं जनवरी-फरवरी 2025 के आसपास इसकी शूटिंग शुरू करूंगी, सोनिया बंसल ने अपनी उत्सुकता के कारणों को साझा करते हुए कहा। आगामी यूनियर्सिटी से एमए करने वाली सोनिया कॉर्पोरेट जगत में अपना करियर शुरू करने के लिए मुंबई चली गईं। हालांकि, उनकी किस्मत और सच्चे जुनून ने उन्हें अभिनय और फैशन इंडस्ट्री की ओर अग्रसर किया। डुबकी, गेम 100 करोड़ का, शूरवीर और धीरा में काम कर चुकीं सोनिया म्यूजिक वीडियो के जगत में भी एक जानी-मानी हस्तियां हैं। उन्हें रियलिटी स्टार शिव ठाकरे के साथ कोई बात नहीं, म्यूजिक वीडियो में देखा गया था। सोनिया बंसल अपनी आने वाली फिल्म चार कदम में बतौर स्टोरी राइटर डेब्यू करने जा रही हैं। इस बारे में बताते हुए सोनिया ने कहा, मुझे न केवल अपने खाली समय में बल्कि यात्रा के दौरान और जब भी संभव हो, फिल्में देखना पसंद है। मैंने कई भाषाओं में बनी फिल्में देखी हैं और एक बात जो मुझे समझ में आई वह यह है कि ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें बताया जाना चाहिए और मैंने चार कदम की कहानी बनाई। यह कई लड़कियों की कहानी है जो बेहतर अवसरों की तलाश में अपने छोटे शहरों से मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में आती हैं, मेरी तरह और वे क्या झेलती हैं। सोनिया ने न केवल फिल्म की कहानी लिखी है बल्कि वह फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं। वह प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रही हैं।

एक्ट्रेस तब्बू अक्षय कुमार अभिनीत हॉरर-कॉमेडी भूत बांग्ला में शामिल हुईं

प्रशंसित अभिनेत्री तब्बू के शनिवार को इस हॉरर-कॉमेडी में शामिल होने के बाद अक्षय कुमार की आगामी फिल्म भूत बांग्ला के लिए उत्सुकता बढ़ गई है। तब्बू ने फिल्म के शीर्षक के साथ एक क्लैपबोर्ड की तस्वीर साझा करके भूत बांग्ला में अपनी भागीदारी की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर प्रोजेक्ट को टीज करते हुए, कू अभिनेत्री ने लिखा, हम यहां बंद हैं। अनुवाद हम यहां बंद हैं। प्रशंसकों ने तुरंत टिप्पणी अनुभाग में तब्बू के प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में अपनी उत्तेजना व्यक्त की। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित, भूत बांग्ला 14 साल के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी को फिर से साथ लाती है। इस जोड़ी ने इससे पहले हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग और भूल भुलैया जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी शैली की है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अक्षय कुमार भूल भुलैया और लक्ष्मी जैसी पिछली सफल फिल्मों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। अंधाधुन और हैदर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर तब्बू से फिल्म में एक अनूठी गहराई जोड़ने की उम्मीद है। भूत बांग्ला का निर्माण शोभा कपूर और एकता आर कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स और अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा किया गया है।



छत्तीसगढ़ बनेगा ऊर्जा और औद्योगिक हब

- » छत्तीसगढ़ में 60 हजार करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप...
- » इन सेक्टरों पर होगा फोकस, सीएम साय से मिले चेयरमैन
- » अडानी ग्रुप 60 हजार करोड़ का करेगा निवेश
- » गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की मीटिंग...
- » अगले चार वर्षों में सीएसआर से 10 हजार करोड़ का निवेश...



अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट के क्षेत्र में 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेश करने की घोषणा की है।

कई क्षेत्रों में होगा निवेश

गौतम अडानी ने कहा-छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में अडानी समूह अपने पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में

6,120 मेगावाट की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। अडानी समूह राज्य में सीमेंट सीएम से चर्चा के दौरान अडानी ने कहा कि अडानी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले चार वर्षों में 10 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

के विकास के लिए अडानी समूह 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा। सीएम से चर्चा के दौरान अडानी ने कहा कि अडानी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले चार वर्षों में 10 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री ने की पहल की सराहना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अडानी समूह के इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि यह निवेश न केवल छत्तीसगढ़ की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

घोषणा करने की जरूरत क्यों

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अडानी की घोषणा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ उनका है। लोहा खदान, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट सब कुछ तो पहले ही अडानी के हवाले कर दिया है। अडानी के बिना घोषणा किए सब कुछ हो रहा है तो उन्हें घोषणा करने की क्या आवश्यकता है।



महिलाओं ने 2 मंत्रियों को बनाया बंधक

40 हजार औरतें हैं करोड़ों की ठगी का शिकार

कोरबा, 12 जनवरी 2025(ए)। फ्लोरामैक्स घोटाले की शिकार महिलाओं ने कोरबा में गौरी-गौरा पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री राम विचार नेताम और लखनलाल देवांगन का घेराव कर उन्हें बाल्मिकी आश्रम में बंधक बना लिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें एक कक्ष में सुरक्षित रखा। प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी के कारण पुलिस और

प्रशासन में हड़कंप मच गया। 6 दिन से जारी प्रदर्शन और महिलाओं की मांग फ्लोरामैक्स कंपनी और निजी बैंकों की सांठगांठ से ठगी गई लगभग 40,000 महिलाओं ने 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए थे। लोन माफी की मांग को लेकर महिलाएं पिछले छह दिनों से तानसेन चौक पर धरना दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान बीमार महिलाओं के अस्पताल ले जाने में भी तनाव की स्थिति बन चुकी है।

प्रदेश की सक्षिप्त खबरें

विधायक इंद्र कुमार साव सड़क हादसे में घायल

मंत्री नेताम ने स्वास्थ्य लाभ की कामना

रायपुर, 12 जनवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के भाटापाया विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंद्र कुमार साव के उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटना में घायल होने का ख़ुद समाचार प्राप्त हुआ। मां महामाया से प्रार्थना है कि विधायक इंद्र कुमार साव एवं उनके परिवारजनों को शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। मां महामाया उन्हें इस कठिन समय में साहस और शक्ति प्रदान करें।

आम जनता को लगा बड़ा झटका

सीमेंट के दाम में हुई बढ़ोतरी

रायपुर, 12 जनवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक और बुरी खबर आई है। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने बीते 11 दिनों में दाम 50 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। अब एक बोरी सीमेंट की कीमत 340 से 350 रुपये के बीच पहुंच गई है, जो जनवरी में 280 से 290 रुपये प्रति बोरी थी।

त्यापम ने जारी किया वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले परीक्षाओं का कैलेंडर

रायपुर, 12 जनवरी 2025 (ए)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए शासकीय सेवा का पिढारा खोल दिया है। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने 2025 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। व्यापम द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से अधिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई हैं, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, एडीईओ से लेकर पुलिस कॉन्स्टेबल, स्टॉफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। ये परीक्षाएं 9 मार्च 2025 से शुरू होकर 21 दिसम्बर 2025 तक चलेंगी। कृषि, पीएचई, नर्सिंग में ये नौकरियां संचालनालय कृषि विभाग के अंतर्गत जिनमें प्रयोगशाला सहायक 09 मार्च 2025 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी 13 अप्रैल 2025, संचालनालय मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक 23 मार्च 2025, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत उप अभियंता (सिविल एवं वि/यां.), तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पी.पी.टी. और पी.एम.सी.ए. का 01 मई, पी.ई.टी. एवं पी.पी.एच.टी. की परीक्षाएं 08 मई 2025 को होंगी।



पीएटी-प्रिन्हीपीटी 15 मई, प्रिन्हीएड एवं प्रिन्हीएलएड 22 मई, बीएससी नर्सिंग 29 मई, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बैसिक नर्सिंग की परीक्षाएं 05 जून 2025 को होंगी। इसी प्रकार सहायक विकास विस्तार अधिकारी 15 जून, नगर सैनिक का 22 जून 2025 को परीक्षा संभावित है। लोक निर्माण विभाग में उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियंता (विद्युत, यांत्रिकी) पदों के लिए परीक्षा तिथि 13 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग में उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) पद के लिए परीक्षा 20 जुलाई, आयुक्त आबकारी में आबकारी आरक्षक पद के लिए 27 जुलाई, उच्च शिक्षा संचालनालय में प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए परीक्षा 03 अगस्त, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में डाकैरूम असिस्टेंट, पेस्टिंग बॉय, ऑर्गनाइजर, इंकमैन इंकर, जूनियर बाईंडर, हमाल, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, भृत्य, डेल्वर (समूह-6) पदों के लिए परीक्षा 31 अगस्त तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) एवं 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कनिष्ठ प्रबंधक- (2) (कंसट्रक्शन, मेटेनॅस), उप प्रबंधक (उपयंत्रो), कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (कृषि विशेषज्ञ), कनिष्ठ प्रबंधक- (2), (आईटी, प्रोग्रामर), कनिष्ठ संवर्ग (आईटी विशेषज्ञ), उप प्रबंधक (प्रोग्रामर) एवं सहायक प्रबंधक (सहायक प्रोग्रामर) पदों की परीक्षा तिथि 7 सितम्बर 2025 निर्धारित की गई है। डेड्स पुलिस विभाग अंतर्गत आरक्षक संवर्ग 14 सितम्बर, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स 21 सितम्बर एवं वार्ड बॉय एवं वार्ड आया 12 अक्टूबर और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं महिला 09 नवम्बर 2025 को परीक्षाएं आयोजित होंगी। मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के विभिन्न पदों पर 30 नवम्बर, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन 07 दिसम्बर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर अंतर्गत अनुवादक 14 दिसम्बर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत केमिस्ट पदों के लिए 21 दिसम्बर को संभावित परीक्षा तिथि जारी की गई है।

केंद्र सरकार ने कर में हिस्सेदारी के रूप में राज्य सरकारों को 1,73,030 करोड़ रुपए जारी किए



रायपुर, 12 जनवरी 2025(ए)। केंद्र सरकार ने कर में हिस्सेदारी के रूप में राज्य सरकारों को 1,73,030 करोड़ रुपए जारी किए, जो कि 2024 के दिसंबर महीने में जारी हुए 89,086 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से अधिक है। 26

राज्यों को जारी हुई राशि घोषित पैकेज के तहत दी गई है जिसमें से छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण प्रक्रिया में 5895.13 करोड़ रुपए मिले हैं जिसपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। एक्स पर ट्वीट करते हुए सीएम साय ने लिखा कि कर हस्तांतरण प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ को 75895.13 करोड़ की अग्रिम किस्त जारी करने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का सहृदय धन्यवाद, यह राशि प्रदेश में पूंजीगत व्यय को गति प्रदान करने के साथ ही, विकसित एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिससे निश्चित ही प्रदेश में जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

बकाएदारों पर सख्ती की तैयारी

विजली का बिल भुगतान नहीं करने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना



रायपुर, 12 जनवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CPDCL) बकायादारों पर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए बिजली बिल बकाया लगाने वाले बिजली कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल न जमा करने पर उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिजली कानून के तहत कार्रवाई के लिए बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबर पर बकाया बिल जमा करने का मैसेज भेज रहे हैं। इसके बाद भी उपभोक्ता बकाया बिल जमा नहीं करने पर ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल न जमा करने पर उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबर पर बकाया बिल जमा करने का मैसेज भेज रहे हैं। इसके बाद भी उपभोक्ता बकाया बिल जमा नहीं करने पर ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल न जमा करने पर उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

अभियंता एम. जामुलकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी। बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल न जमा करने पर उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

रायपुर ननि के उपायुक्त के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक



शासन ने सीएमओ बनाकर भेजा था महसमुद

बिलासपुर, 12 जनवरी 2025 (ए)। नगर निगम रायपुर में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर कृष्णा खटिक के तबादले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अपने तबादले को नियमों का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। नगरीय प्रशासन विभाग ने हाल ही में अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। सूची में शामिल कृष्णा खटिक ग्रेड 'ए' के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनको महसमुद नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर भेजा गया। यह पद ग्रेड 'ए' के अधिकारियों के लिए निर्धारित है, जो खटिक के वर्तमान पद से जूनियर है। अपने तबादले को बताया डिमोशन..! डिप्टी कमिश्नर खटिक ने एडवोकेट संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि यह तबादला आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के 2017 के सेवा शर्त नियमों का उल्लंघन है। खटिक ने बताया कि महसमुद सीएमओ का पद उनके ग्रेड से जूनियर अधिकारियों के लिए है और उनका ट्रांसफर एक तरह से डिमोशन है। तबादला रोक, महान जांच के लिए आदेश जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगाई और याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों के विपरीत बताते हुए मामले को गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला राज्य शासन की सेवा नीति और नियमों के पालन पर सवाल खड़े करता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अनुभव और योग्यता के अनुसार पदस्थ किया जाए।

छत्तीसगढ़ में गोकशी पर गरमाई सियासत

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप

रायपुर, 12 जनवरी 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले गोकशी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। रायपुर के मोमिनपारा में गौमांस बिन्नी के मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में पूर्व छरूभूषण बघेल ने भी एक आरोपी के साथ भाजपा नेताओं की तस्वीरों को पोस्ट किया है।



गोकशी के आरोपियों को लेकर पहले भाजपा ने कांग्रेस नेताओं से संबंध का दावा किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मुख्य आरोपी का भाजपा से कनेक्शन होने की बात कही है।

अमरजीत भगत का बड़ा बयान

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, हिंदुस्तान के बड़े गौ तस्करों से भाजपा का संबंध है। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद गौ तस्कर नहीं रुक रही। भाजपा को गौ तस्कर कंपनियों से फंडिंग मिल रही है।

भूपेश बघेल ने किया ये ट्वीट

इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें गोकशी का एक आरोपी था। लेकिन अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मुख्य आरोपी का भाजपा से कनेक्शन होने की बात कही है।

सविदा पदों पर निकली बंपर भर्ती

दुर्ग, 12 जनवरी 2025 (ए)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिले की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/जिला स्वास्थ्य समिति जिला दुर्ग के अंतर्गत सविदा पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में पूंजीकृत डाक/स्पेड पोस्ट के माध्यम से 25 जनवरी 2025 तक कार्यालयीन समय में सायं 05.30 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिकारी मनोज दानी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में पूंजीकृत डाक/स्पेड पोस्ट के माध्यम से 25 जनवरी 2025 तक कार्यालयीन समय में सायं 05.30 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बीजापुर नेशनल पार्क क्षेत्र में 3 नक्सली डेर

सीएम साय ने दी बधाई

रायपुर, 12 जनवरी 2025(ए)। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पर सीएम विष्णुदेव साय नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने बताया कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ आज हुई मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सलियों को मारे जाने की

खबर है। जवानों के अदम्य साहस को नमन करता हूँ। नक्सलवाद के पूर्णतः खत्म के लिए हमारे अभियान को मिल रही यह सफलता, मार्च 2026 तक देश-प्रदेश से नक्सलवाद की समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करती है। बस्तर संभाग में शांति एवं खुशहाली की स्थापना हेतु डबल इंजन की सरकार दृढ़ संकल्पित है।